सान्ध्य हिन्दी दैनिक

जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

वर्ष - 03 | अंक - 162 | जौनपुर, गुरूवार, 30 जनवरी 2025 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज - 4 | मूल्य - 2 रूपये

संक्षिप्त समाचार

झारखंड के मुख्यमंत्री ने महाकुंभ में मची भगदड़ पर शोक जताया

झारखंड, (एजेंसी)। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान मची भगदड़ में श्रद्धालुओं की मौत पर गहरा शोक प्रकट किया है। सोरेन ने इस दुखद घटना में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की। मौनी अमावस्या के अवसर पर बुधवार तड़के संगम क्षेत्र में भगदड़ मच गयी, करोड़ो श्रद्धालु स्नान के लिए संगम तट पर उमड़े थे। इस हादसे में कई लोगों की जान चली गयी। मुख्यमंत्री सोरेन ने कहा कि महाकुंभ में भगदड़ की दुखद खबर सुनकर मन व्यथित है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट कर कहा, मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं। इस घटना में घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। उन्होंने उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार इस घटना की गहन जांच करेगी और भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। सोरेन ने कहा, हमें ऐसी त्रासदियों से सबक लेना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों। इसके लिए उचित सुरक्षा प्रबंध किए जाने चाहिए।

तेल फैक्टरी में बॉयलर फटने से दो मजदूरों की मौत

कर्नाटक, (एजेंसी)। ुमकुरु में अंतरासनहल्ली औद्योगिक क्षेत्र में 'राइस ब्रान' तेल की फैक्टरी के बॉयलर में मंगलवार को कथित तौर पर विस्फोट होने से दो मजदूरों की मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। उसने बताया कि मृतकों की पहचान बिहार के चंदन शर्मा (24) और संतोष (27) के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, विस्फोट शाम करीब साढ़े पांच बजे हुआ। पुलिस ने बताया कि बॉयलर में विस्फोट होने से मजदूर ऊंचाई से नीचे गिर गए, जिससे उनकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक, भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।

मौनी अमावस्या पर श्रद्धालुओं के लिए 360 ट्रेनें चला रहा रेलवे

नई दिल्ली, (एजेंसी)। रेलवे मौनी अमावस्या पर महाकुंभ मेले में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए 190 विशेष ट्रेनों सहित 360 ट्रेनें संचालित कर रहा है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश कुमार ने मंगलवार को यह जानकारी दी। बुधवार को मौनी अमावस्या पर होने वाले 'अमृत स्नान' के चलते महाकुंभ में लगभग 10 करोड़ तीर्थयात्रियों के आने की उम्मीद है। कुमार ने यहां संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि रेलवे ने तीर्थयात्रियों की अभूतपूर्व आमद को देखते हुए व्यापक कदम उठाए हैं और महाकुंभ के सबसे शुभ दिन 'मौनी अमावस्या' के लिए ट्रेन सेवाओं में उल्लेखनीय वृद्धि करने का निर्णय लिया है। कुमार ने कहा, "रेलवे इस अवसर के लिए 360 ट्रेनें चला रहा है, जिनमें 190 विशेष ट्रेनें शामिल हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को संभालने के लिए तीन जोन – उत्तर रेलवे, पूर्वोत्तर है।

कुछ समय के लिए स्नान की प्रक्रिया में रुकावट आई, पर अब सब ठीक है : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

नई दिल्ली, (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए महाकुंभ में हुई भगदड़ की घटना का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आज की चुनाव सभा को संबोधित करने से पहले मैं महाकुंभ में जो दुःखद हादसा हुआ है, उस हादसे में हमें कुछ पुण्यात्माओं को खोना पड़ा है, कई लोगों को चोटें भी आई हैं। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति संवदेना व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। मैं उत्तर प्रदेश सरकार के साथ निरंतर संपर्क में हूं। मौनी अमावस्या की वजह से करोड़ों श्रद्धालु आज वहां पहुंचे हुए हैं। कुछ समय के लिए स्नान की प्रक्रिया में रुकावट आई थी, लेकिन अब कई घंटों से सुचारू रूप से यात्री स्नान कर रहे हैं। मैं फिर एक बार उन परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। इससे पहले पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म श्एक्सश पर कहा, श्प्रयागराज महाकुंभ में हुआ हादसा अत्यंत दुखद है। जिन श्रद्धालुओं ने अपने परिजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। इसके साथ ही मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हरसंभव मदद में जुटा हुआ है। इस सिलसिले में मैंने मुख्यमंत्री योगी से बातचीत की है और मैं लगातार राज्य सरकार के संपर्क में हूं। मामले से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार महाकुंभ की स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और राज्य सरकार से लगातार संपर्क में हैं। उन्होंने अब तक तीन बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की है। उन्होंने स्थिति सामान्य करने और राहत कार्य के लिए दिशा–निर्देश दिए हैं। इस बीच महाकुंभ मेले में भगदड़ जैसी घटना होने के बावजूद श्रद्धालुओं का आना जारी है और मेला प्रशासन के मुताबिक, आज दोपहर 12 बजे तक करीब 4.24 करोड़ श्रद्धालु पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। आज तक पवित्र डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं की कुल संख्या 20 करोड़ को पार कर गई है। एक अधिकारी ने बताया कि मेला क्षेत्र में भारी संख्या में लोगों का आना जारी है।

कानून के उल्लंघन पर दर्ज मुकदमों और आरोप–पत्रों की संख्या पूछी : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को तीन तलाक कानून के विरोध में दायर याचिकाओं पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिए कि मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम का उल्लंघन करके जीवनसाथी को तीन तलाक देने वाले पुरुषों के खिलाफ दर्ज एफआईआर और आरोपपत्रों की संख्या की जानकारी दी जाए। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने कानून की सांविधानिकता को चुनौती देने वाली 12 याचिकाओं पर सुनवाई की। कोर्ट ने केंद्र और अन्य पक्षों से इन याचिकाओं पर अपने लिखित दलीलें दाखिल करने को भी कहा। पीठ ने कहा कि केंद्र सरकार मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम 2019 की धारा 3 और 4 के तहत लंबित कुल एफआईआर और आरोप पत्र की संख्या दाखिल करेगी। वहीं पक्षकार अपने तर्क के समर्थन में तीन पेज में लिखित प्रस्तुतियां भी दाखिल करेंगे। पीठ ने याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई 17 मार्च से शुरू होने वाले सप्ताह में तय की

है। देश में 30 जुलाई 2019 को तीन तलाक को लेकर कानून बनाया गया था। इसके तहत तलाक–ए–बिद्दत यानी एक बार में तीन तलाक देना गैर कानूनी है। तीन तलाक संज्ञेय अपराध मानने का प्रावधान किया गया है। कानून के तहत तीन तलाक को अवैध और अमान्य घोषित किया गया है तथा इसके लिए पति को तीन साल की जेल की सजा होगी। खुद को सुन्नी विद्वानों का संघ बताने वाले केरल के जमीयतुल उलेमा ने मुस्लिम महिला अधिनियम 2019 को असांविधानिक बताते हुए याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि जब सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक को अमान्य करार कर दिया है तो इसे अपराध घोषित नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त 2017 को एक ऐतिहासिक फैसले में तीन तलाक को असांविधानिक करार दिया था। अलग–अलग धर्मों वाले 5 जजों की बेंच ने 3–2 से फैसला सुनाते हुए सरकार से तीन तलाक पर छह महीने के अंदर कानून लाने को कहा था। दो जजों ने इसे असंवैधानिक कहा था।

झारखंड के मुख्यमंत्री ने महाकुंभ में मची भगदड़ पर शोक जताया

नई दिल्ली, (एजेंसी)। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान मची भगदड़ में श्रद्धालुओं की मौत पर गहरा शोक प्रकट किया है। सोरेन ने इस दुखद घटना में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की। मौनी अमावस्या के अवसर पर बुधवार तड़के संगम क्षेत्र में भगदड़ मच गयी, करोड़ो श्रद्धालु स्नान के लिए संगम तट पर उमड़े थे। इस हादसे में कई लोगों की जान चली गयी। मुख्यमंत्री सोरेन ने कहा कि महाकुंभ में भगदड़ की दुखद खबर सुनकर मन व्यथित है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट कर कहा, मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं। इस घटना में घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। उन्होंने उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार इस घटना की गहन जांच करेगी और भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। सोरेन ने कहा, हमें ऐसी त्रासदियों से सबक लेना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों। इसके लिए उचित सुरक्षा प्रबंध किए जाने चाहिए।

कैबिनेट ने 16300 करोड़ रुपये के खनिज मिशन को मंजूरी दी

नई दिल्ली, (एजेंसी)। केंद्रीय मंत्रीमंडल ने 16,300 करोड़ रुपये के खनिज मिशन को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को इसका एलान किया। इसके साथ ही कैबिनेट ने सी श्रेणी के भारी गुड़ से उत्पादित इथेनॉल की एक्स–मिल कीमत 56.28 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 57.97 रुपये प्रति लीटर करने को भी मंजूरी दे दी है। सरकार की ओर से निर्धारित इथेनॉल की कीमतें 2022–23 इथेनॉल आपूर्ति वर्ष (नवंबर–अक्तूबर) के बाद से नहीं बढ़ाई गई थी। गन्ने के रस, बी–हैवी गुड़ और सी–हैवी गुड़

से उत्पादित इथेनॉल की वर्तमान दरें क्रमशः 65.61 रुपये, 60.73 रुपये और 56.28 रुपये प्रति लीटर हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को इस वर्ष 31 अक्तूबर को समाप्त होने वाली 2024–25 अवधि के लिए इथेनॉल की कीमतों का एलान किया। सी श्रेणी के भारी गुड़ से प्राप्त इथेनॉल की एक्स–मिल कीमत 1.69 रुपये बढ़ाकर 57.97 रुपये प्रति लीटर करने को मंजूरी दी गई। बी श्रेणी के भारी गुड़ और गन्ना रसध्चीनीध्चीनी सिरप से उत्पादित इथेनॉल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया। इनकी कीमतें क्रमशः 60.73 रुपये प्रति लीटर और 65.61 रुपये प्रति लीटर पर अपरिवर्तित रखी गईं। इथेनॉल की कीमतें बढ़ाने का फैसला आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने ली। इसकी जानकारी देते हुए सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इथेनॉल आपूर्ति वर्ष (ईएसवाई) 2024–25 के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) के लिए इथेनॉल खरीद मूल्य में संशोधन को मंजूरी दी गई है। सरकार ने पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य भी 2030 से घटाकर इथेनॉल वर्ष 2025–26 कर दिया है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है, ष्इस दिशा में एक कदम उठाते हुए, तेल विपणन कंपनियों ने चालू ईएसवाई 2024–25 के दौरान 18 प्रतिशत इथेनॉल के मिश्रण की योजना बनाई है। इस बीच, चीनी और इथेनॉल से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में तेजी दिखी है। ईआईडी–पैरी, श्री रेणुका शुगर्स, बलरामपुर चीनी मिल्स और त्रिवेणी इंजीनियरिंग के शेयरों में बीएसई सेंसेक्स पर 3.7%, 4.5%, 2.5% और 2.3% की बढ़त दर्ज की गई। सेंसेक्स 0.62% की बढ़त दिखी।

नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी, अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी

नई दिल्ली, (एजेंसी)। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को मीडियाकर्मियों को कई परियोजनाओं पर कैबिनेट द्वारा लिए गए प्रमुख फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने कहा, कैबिनेट ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन के लिए 16,300 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16,300 करोड़ रुपये के व्यय और पीएसयू आदि द्वारा 18,000 करोड़ रुपये के अपेक्षित निवेश के साथ राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन (एनसीएमएम) के शुभारंभ को मंजूरी दे दी है। मंत्री ने बताया कि आत्मनिर्भर भारत पहल के हिस्से के रूप में, और उच्च तकनीकी उद्योगों, स्वच्छ ऊर्जा और रक्षा में महत्वपूर्ण खनिजों की अपरिहार्य भूमिका को पहचानते हुए, भारत सरकार ने महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र में चुनौतियों का समाधान करने के लिए पिछले दो वर्षों में कई पहल की हैं। सरकार ने एक बयान में कहा कि महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता के लिए एक प्रभावी ढांचा स्थापित करने की आवश्यकता है। इस दृष्टिकोण के अनुरूप, वित्त मंत्री ने 23 जुलाई 2024 को 2024–25 के केंद्रीय बजट में क्रिटिकल मिनरल मिशन की स्थापना की घोषणा की। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन, मूल्य श्रृंखला के सभी चरणों को शामिल करेगा, जिसमें खनिज अन्वेषण, खनन, लाभकारी, प्रसंस्करण और अंतिम उत्पादों से पुनर्प्राप्ति शामिल है। यह मिशन देश के भीतर और इसके अपतटीय क्षेत्रों में महत्वपूर्ण खनिजों की खोज को तेज करेगा।

यमुना जल विवाद के बीच आतिशी का एलजी पर पलटवार

नई दिल्ली, (एजेंसी)। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने बुधवार को एक पत्र के जरिए उपराज्यपाल वीके सक्सेना पर पलटवार किया है। आतिशी ने कहा कि उपराज्यपाल के रूप में, उन्हें हट जाना चाहिए और उन लोगों के लिए रास्ता बनाना चाहिए जो राष्ट्रीय राजधानी के निवासियों के हित में कार्य करने के इच्छुक हैं। सीएम आतिशी का उपराज्यपाल को पत्र ऐसे समय आया है, जब एक दिन पहले ही सक्सेना ने उन्हें पत्र लिखकर आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की उस टिप्पणी पर चिंता व्यक्त की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि हरियाणा सरकार द्वारा यमुना नदी को जहर दिया जा रहा है। उपराज्यपाल ने दिल्ली की मुख्यमंत्री को संकीर्ण राजनीति से ऊपर उठने की सलाह दी थी और पड़ोसी राज्यों के बीच कलह पैदा करने वाले बयानों की निंदा करने में विफल रहने के लिए उनकी आलोचना की थी। बुधवार को एलजी को लिखे पत्र में, सीएम आतिशी ने कहा, षदिल्ली के पानी में खतरनाक रूप से उच्च अमोनिया स्तर के गंभीर मुद्दे को संबोधित करने के बजाय, आपने आधारहीन आरोप लगाए हैं और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में अपनी पूरी विफलता से ध्यान हटाने के लिए झूठी कहानी गढ़ी है। उन्होंने सक्सेना से कहा कि वह ष्अपने राजनीतिक आकाओं (भाजपा) के आदेशों का पालन न करें बल्कि राष्ट्रीय राजधानी में लोगों के कल्याण को प्राथमिकता दें। सीएम आतिशी ने लिखा कि एलजी ने सार्वजनिक हित को प्राथमिकता देने के बजाय अपने राजनीतिक हित के आगे झुक गए। उन्होंने एलजी सक्सेना पर हमला करते हुए कहा कि दिल्ली जल बोर्ड के नियंत्रण में रहने के बावजूद, उन्होंने इस मुद्दे को हल करने के लिए न तो सार्थक कदम उठाए और न ही सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए तात्कालिकता का प्रदर्शन किया, लेकिन राजनीतिक एजेंडे को प्राथमिकता दी। इससे पहले दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना

ने मुख्यमंत्री आतिशी को पत्र लिखकर कहा कि यमुना के पानी में जहर मिलाने और राष्ट्रीय राजधानी में "नरसंहार" का प्रयास किए जाने के आम आदमी पार्टी (आप) के प्रमुख अरविंद केजरीवाल के आरोप अत्यंत आपत्तिजनक और दुर्भाग्यपूर्ण हैं तथा राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने के समान हैं। सक्सेना ने मीडिया में आई खबरों का हवाला देते हुए कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली हरियाणा सरकार पर यमुना नदी में जहर मिलाने और दिल्ली में "नरसंहार" का प्रयास करने के केजरीवाल के आरोप "अत्यंत आपत्तिजनक, दुर्भाग्यपूर्ण और अवांछनीय" हैं।

अखिलेश यादव की मांग, तत्काल सेना को सौंपी जाए महाकुंभ का प्रशासन और प्रबंधन

नई दिल्ली, (एजेंसी)। समाजवादी पार्टी (सपा) प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार के आयोजन के संचालन में विश्वास की कमी का हवाला देते हुए, महाकुंभ मेले के प्रशासन और प्रबंधन को तत्काल भारतीय सेना को सौंपने की मांग की है। उनकी यह प्रतिक्रिया आज सुबह–सुबह प्रयागराज के महाकुंभ में भगदड़ जैसी स्थिति के बाद आई है। अखिलेश ने एक्स पर लिखा कि महाकुंभ में आए संत समाज और श्रद्धालुओं में व्यवस्था के प्रति पुनर्विश्वास जगाने के लिए ये आवश्यक है कि उप्र शासन–प्रशासन के स्थान पर महाकुंभ का प्रशासन और प्रबंधन तत्काल सेना को सौंप देना चाहिए। अखिलेश यादव ने ने कहा कि 'विश्वस्तरीय व्यवस्था' करने के प्रचार करते हुए दावों की सच्चाई अब जब सबके सामने आ गयी है, तो जो लोग

इसका दावा और मिथ्या प्रचार कर रहे थे, उन्हें इस हादसे में हत हुए लोगों की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपना पद त्याग देना चाहिए। अखिलेश ने लिखा कि महाकुंभ में अव्यवस्थाजन्य हादसे में श्रद्धालुओं के हताहत होने का समाचार बेहद दुखद है। श्रद्धांजलि! सरकार से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी सरकार से अपील है कि गंभीर रूप से घायलों को एअर एंबुलेंस की मदद से निकटतम सर्वश्रेष्ठ हॉस्पिटलों तक पहुंचाकर तुरंत चिकित्सा व्यवस्था की जाए। सपा नेता ने आगे कहा कि मृतकों के शवों को चिन्हित करके उनके परिजनों को सौंपने और उन्हें उनके निवास स्थान तक भेजने का प्रबंध किया जाए। लोग बिछड़ गये हैं, उन्हें मिलाने के लिए त्वरित प्रयास किये जाएं। हैलीकाप्टर का सदुपयोग करते हुए निगरानी बढ़ाई जाए। सतयुग से चली आ रही 'शाही स्नान' की अखण्ड–अमृत परंपरा को निरंतर रखते हुए, राहत कार्यों के समानांतर सुरक्षित प्रबंधन के बीच 'मौनी अमावस्या के शाही स्नान' को संपन्न कराने की व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं से भी हमारी अपील है कि वो इस कठिन समय में संयम और धैर्य से काम लें और शांतिपूर्वक अपनी तीर्थयात्रा संपन्न करें। सरकार आज की घटना से सबक लेते हुए श्रद्धालुओं के रुकने, ठहरने, भोजन–पानी व अन्य सुविधाओं के लिए अतिरिक्त प्रबंध करे।

राहुल गांधी ने वीआईपी कल्चर को ठहराया दोषी अखिलेश का गुस्सा फूटा

नई दिल्ली, (एजेंसी)। इसी बीच कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि योगी आदित्यनाथ प्रबंधन और कुप्रबंधन से ज्यादा आत्मप्रचार पर ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि अव्यवस्था और प्रशासन द्वारा ध्याम कम दिए जाने के कारण ऐसा हुआ है। वीआईपी मूवमेंट पर अधिक ध्यान देने के कारण ये हादसा हुआ है। महाकुंभ पूरा होने में काफी समय शेष है और अभी कई शाही स्नान बाकी है। ऐसे में सरकार को अपनी व्यवस्था में सुधार करना चाहिए। महाकुंभ में ऐसी घटना दोबारा ना हो इसका ध्यान रखना चाहिए। वीआईपी कल्चर पर रोक लगाना जरुरी है, ताकि आम जनता की जरुरतों को पूरा करने पर ध्यान जा सके। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी महाकुंभ पर हजारों करोड़ रुपये खर्च करने के बाद आधे अधूरे इंतजाम करने पर सवाल उठाया है। आधे अधूरे इंतजाम, वीआईपी मूवमेंट, असल प्रबंधन से अधिक आत्मप्रचार करने की जगह जरुरतों को पूरा करना चाहिए। हजारों करोड़ रुपये खर्च करने के बाद ऐसा कुप्रबंधन निंदनीय है। कुंभ के आयोजन के दौरान श्रद्धालुओं के आवास, भोजन, प्राथमिक चिकित्सा और आवागमन की व्यवस्था का विस्तार होना चाहिए। वीआईपी कल्चर और वीआईपी लोगों के आवागमन पर रोक लगनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भगदड़ के बाद कहा कि विश्व स्तरीय व्यवस्था का झूठा प्रचार राज्य सरकार कर रही थी। उन्होंने कहा कि विश्व स्तरीय व्यवस्था के दावों के पीछे की सच्चाई सामने आ गई है। जिन लोगों ने विश्व स्तरीय व्यवस्था का दावा किया था इस हादसे की जिम्मेदारी उन्हें लेनी चाहिए। इन लोगों को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार को महाकुंभ का प्रबंधन भारतीय सेना को सौंपना चाहिए। ऐसे में संत समुदाय और श्रद्धालुओं में व्यवस्था के प्रति विश्वास दोबारा पैदा हो सके।

संपादकीय

जलवायु संकट में बच्चे

यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है कि ग्लोबल वार्मिंग ने हमारे दरवाजे पर दस्तक दे दी है। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी से जहां सामान्य जन–जीवन बाधित है, वहीं खेती किसानी पर भी नया संकट मंडरा रहा है। खासकर भारत जैसे देश में जहां अधिकांश कृषि मानसूनी बारिश पर निर्भर है। सबसे बड़ा संकट हमारे कृषि क्षेत्र पर है, जहां उत्पादकता घटने से हमारी खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ती नजर आ रही है। लेकिन अब 'नेचर क्लाइमेट चेंज' पत्रिका में प्रकाशित वह रिपोर्ट चौंकाती है, जिसमें खुलासा किया गया है कि भारत में करीब साढ़े पांच करोड़ बच्चों की शिक्षा हीटवेव से बाधित हुई है। यह संकट यूं तो पूरी दुनिया में है लेकिन दक्षिण एशिया के अन्य देशों के मुकाबले दुनिया की सर्वाधिक जनसंख्या वाले भारत में इसका ज्यादा प्रभाव देखा गया है। रिपोर्ट दावा करती है कि वर्ष 2024 में लू के कारण भारत में शिक्षा व्यवस्था पर खासा प्रतिकूल असर पड़ा है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ की रिपोर्ट 'लर्निंग इंटरप्टेड रू ग्लोबल स्नैपशॉट ऑफ क्लाइमेट–रिलेटेड स्कूल डिसरप्शंस इन 2024' में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। उल्लेखनीय है कि अब तक कृषि व मौसम के चक्र पर ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों के अध्ययन निष्कर्ष तो सामने आए, लेकिन बच्चों के प्रति कोई ऐसा संवेदनशील अध्ययन सामने नहीं आया था। जिसने जहां एक ओर अभिभावकों की चिंता बढ़ा दी, वहीं सरकार पर दबाव बनाया कि वह बच्चों व शिक्षा पर जलवायु परिवर्तन से होने वाले असर को कम करने के लिये कारगर नीतियां यथाशीघ्र बनाये। निस्संदेह, यह अध्ययन देश के नीति–नियंताओं को चेताता है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से बच्चों को बचाने के लिये शिक्षा ही नहीं स्वास्थ्य आदि अन्य क्षेत्रों में व्यापक पैमाने पर काम करने की जरूरत है। शिक्षाविदों के साथ ही चिकित्सा बिरादरी के लोगों को भी इस ज्वलंत मुद्दे पर मंथन करने की जरूरत है क्योंकि अध्ययन में वर्ष 2050 तक बच्चों पर गर्म हवाओं का असर आठ गुना तक बढ़ने की आशंका है। बीता साल एक सदी से अधिक अवधि के बाद का सबसे गर्म साल घोषित किया गया है। मौसम विभाग ने सूचित किया था कि वर्ष 2024 वर्ष 1901 के बाद सबसे अधिक गर्म साल रहा है। जो ग्लोबल वार्मिंग के भयावह संकट को ही उजागर करता है। यह भी कि यदि देश–दुनिया में ग्रीन हाउस गैसों के नियंत्रण के लिये वैश्विक सहमति शीघ्र नहीं बनती तो आने वाले वर्षों में तापमान में और वृद्धि हो सकती है। जो न केवल बच्चों की शिक्षा बल्कि उनके स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर डालेगा। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ने चेतावनी दी है कि ग्लोबल वार्मिंग संकट से बच्चों की शिक्षा बाधित होने से उनके भविष्य पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। लू की गर्म लहरों के बीच छोटे बच्चों का स्कूल जाना संभव नहीं हो पाता। अभिभावक भी पढ़ाई की तुलना में उनके जीवन को प्राथमिकता देते हैं। ऐसे में समय रहते स्कूलों के समय निर्धारण में परिवर्तन और बढ़ती गर्मी से जुड़ी सावधानियों के प्रति जागरूकता बढ़ाकर इस संकट का मुकाबला किया जा सकता है। इसके अलावा देश में जलवायु परिवर्तन प्रभावों का हमारे जन–जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों के मूल्यांकन के लिये व्यापक अध्ययन व शोध करने की जरूरत महसूस की जा रही है। यदि समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो इसके प्रभाव दीर्घकालीन हो सकते हैं। उल्लेखनीय है कि यूनीसेफ ने जिस अध्ययन का हवाला दिया है वह ओस्लो यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के निष्कर्ष हैं। यह कोशिश भारत के विश्वविद्यालयों व शोध संस्थानों द्वारा की जानी चाहिए ताकि निष्कर्ष भारतीय परिस्थितियों के हिसाब से स्वदेशी अध्ययन के चलते अधिक प्रमाणिक हों। लेकिन इसके अलावा ओस्लो विश्वविद्यालय के अध्ययन में उल्लेखनीय तथ्य यह है कि भारत को ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों की दृष्टि से अधिक संवेदनशील बताया गया है।

सवालों में यूसीसी का फैसला

मोहन

27 जनवरी से उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफार्म सिविल कोड (यूसीसी) लागू हो गया है। भाजपा शुरुआत से यूसीसी की वकालत करती आई है। उसके चुनावी घोषणापत्र में यूसीसी लागू करने का वादा किया जा चुका है। फिलहाल भाजपा शासित उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। जिस तरह से इसे भाजपा की बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश किया जा रहा है, आश्चर्य नहीं कि जल्द ही दूसरे भाजपा शासित राज्यों में ऐसा ही फैसला लिया जाए। यूसीसी लागू होने के बाद उत्तराखंड में सभी धर्मों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र लड़कों के लिए 21 साल और लड़कियों के लिए 18 साल होगी, तलाक के नियम और प्रक्रियाएं एक समान होंगी, वहीं दूसरी शादी की अनुमति तभी होगी, जब पहली पत्नी से तलाक हो चुका हो या वह नहीं रही हो। अब सभी धर्मों में बेटियों को माता–पिता की संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा और सभी धर्मों की महिलाओं को गोद लेने का समान अधिकार भी होगा। यूसीसी में एक बड़ा फैसला लिव–इन रिलेशनशिप यानी बिना विवाह के सहजीवन में रहने वालों के लिए है, ऐसे जोड़ों को अब रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और इसके लिए दोनों का बालिग होना जरूरी है, साथ ही उनके बीच खून का रिश्ता या पारिवारिक संबंध नहीं होना चाहिए। यूसीसी में प्रावधान है कि अगर लिव इन में रहते हुए बच्चा होता है, तो उसे वैध माना जाएगा। लिव–इन रिश्ता खत्म होने पर महिला भरण–पोषण और गुजारा भत्ता का दावा कर सकेगी। अगर किसी ने एक महीने के भीतर लिव–इन का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, तो उसे 3 महीने की जेल और 10 हजार रुपये का जुर्माना हो सकता है। गलत जानकारी देने पर जुर्माना बढ़कर 25 हजार रुपये तक हो सकता है। यूसीसी में उत्तराखंड की अनुसूचित जनजातियों को छूट दी गई है, इन्हें संविधान के भाग 21 के तहत संरक्षण प्राप्त है। ये जनजातियां राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 3 प्रतिशत हैं। भाजपा यूसीसी को प्रगतिकारी और महिला समर्थक कानून के तौर पर पेश कर रही है। लेकिन बारीकी से पड़ताल करें तो यह भाजपा की तरफ से संविधान बदलने की कोशिश का एक और कदम नजर आएगा। संविधान के भाग चार के अनुच्छेद 44 में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों में कहा गया हैरू श्राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा।य गौरतलब है कि यहां राज्य का तात्पर्य संघ सरकार से है। इसलिए केंद्र सरकार नहीं बल्कि कोई राज्य यूसीसी लागू करे तो यह सीधे तौर पर संविधान की अवहेलना है। प्रधानमंत्री ने पिछले साल जुलाई में मुस्लिम पर्सनल लॉ का जिक्र करते हुए कहा था कि, श्एक घर में, यदि एक सदस्य के पास एक कानून है और दूसरे सदस्य के पास दूसरा कानून है, तो क्या वह घर, परिवार चल सकता है? तो दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चलेगा?य लेकिन अब उन्हीं की नाक के नीचे एक राज्य ने यूसीसी लागू कर दिया, यानी उत्तराखंड में एक व्यवस्था लागू हो गई और बाकी राज्य में दूसरी व्यवस्था लागू है। अब क्या श्री मोदी ये बताएंगे कि एक राज्य के नागरिकों को अलग कानून और दूसरे राज्य के नागरिकों को अलग कानून का पालन क्यों करना पड़ रहा है। उत्तराखंड के यूसीसी में संविधान का हवाला देते हुए अनुसूचित जनजातियों को अलग रखा गया है। लेकिन सरकार को संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 क्यों नहीं याद रहे जो धार्मिक स्वतंत्रता के मूल अधिकारों की व्याख्या करते हैं। अनुच्छेद 25 कहता है, श्सभी व्यक्ति अंतरात्मा की स्वतंत्रता और सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने के समान रूप से हकदार हैंय। वहीं अनुच्छेद 26 कहता है कि सभी संप्रदाय धर्म के मामलों में अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन कर सकते हैं। लेकिन यूसीसी के तहत इस अधिकार को खत्म किया जा रहा है।

उत्तराखंड सरकार के फैसले को जमीयत उलमा–ए–हिंद ने नैनीताल हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का निर्णय लिया है। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी का मानना है कि यूसीसी न केवल नागरिकों की धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला है, बल्कि पूरी तरह से भेदभाव और पूर्वाग्रह पर आधारित है। जमीयत उलमा–ए–हिंद की इस आपत्ति से जाहिर है कि सरकार ने इस मसले पर राय मशविरा किए बगैर अपनी मर्जी थोपी है। कायदे से किसी महत्वपूर्ण विधेयक पर विपक्ष के साथ व्यापक चर्चा होनी चाहिए, आपत्तियों और आशंकाओं का निराकरण होना चाहिए, लेकिन जिस तरह कृषि कानून थोप दिए गए थे, वैसा ही काम अब उत्तराखंड में हुआ है। बताया जा रहा है कि उत्तराखंड समान नागरिक संहिता विधेयक के मामले में, विपक्षी सदस्यों द्वारा विरोध किए जाने के बावजूद कि उन्हें 192 पृष्ठों के मसौदे का अध्ययन करने के लिए कोई समय नहीं दिया गया, इसे पारित कर दिया गया। न्यायमूर्ति बलबीर सिंह चौहान की अध्यक्षता वाले 21 वें विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता को खारिज करते हुए कहा था कि यह न तो आवश्यक है और न ही वांछनीय है। आज उनकी बात फिर सही होती दिख रही है। क्योंकि उत्तराखंड का यूसीसी नैतिक पुलिसिंग करने का एक और औजार नजर आ रहा है। लिव इन रिलेशनशिप में जो शर्तें लागू की गई हैं या विवाह के पंजीकरण में जिस तरह जोड़े के सभी व्यक्तिगत विवरणों और अस्वीकृति के कारणों के विवरण के साथ रजिस्टर को किसी भी व्यक्ति द्वारा निरीक्षण के लिए खुला रखने का प्रावधान रखा गया है, वह निजता के अधिकार का उल्लंघन है ही, साथ ही वयस्कों को अपनी मर्जी से फैसले लेने पर भी रोका जा रहा है। यूसीसी राज्य के नागरिकों के साथ उन लोगों के लिए भी है जो दो साल से वहां रह रहे हैं यानी अगर कोई नौकरी या पढ़ाई के सिलसिले में दूसरे राज्यों से वहां गया है, उसे उत्तराखंड का कानून मानना पड़ेगा, जबकि उसके अपने राज्य में कोई और प्रावधान रहेगा। साफ है कि यूसीसी के नाम पर संविधान से छेड़छाड़ का मंसूबा भाजपा ने पूरा किया है।

दुनिया की दुखती रग पर चोट दी ट्रंप ने

दिनेश सी.

अमेरिकी राष्ट्रपति का ओहदा संभालते ही डोनाल्ड ट्रंप ने जिन कार्यकारी आदेशों पर सबसे पहले हस्ताक्षर किए उनमें एक है विश्व स्वास्थ्य संगठन से अमेरिका का हटना। आदेश में दलील दी गई है कि यह निर्णय 'चीन के वुहान से शुरू हुई कोविड महामारी और अन्य वैश्विक स्वास्थ्य संकटों को ठीक से न संभाल पाना, फौरी तौर पर जिन सुधारों की जरूरत थी उन्हें करने में विफलता और संगठन के सदस्य देशों के अनुचित राजनीतिक प्रभाव से खुद को मुक्त रख पाने में इसकी 'अक्षमता' के बाद लिया गया है।' आदेश में कहा गया है कि अमेरिका चीन जैसे देशों की तुलना में विश्व स्वास्थ्य संगठन को 'कहीं अधिक' सहायता दे रहा हैदृ चीन की आबादी 1.4 बिलियन है, लेकिन वह बहुत कम राशि का योगदान करता है। ट्रंप के इस फैसले में न केवल अमेरिका बल्कि वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा पर दूरगामी प्रभाव निहितार्थ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रति ऐसी हेठी उनके पहले कार्यकाल के दौरान में भी स्पष्ट थी, जब दुनिया कोविड महामारी की मार से जूझ रही थी। स्थिति को ठीक से न संभालने के लिए उन्होंने इस स्वास्थ्य एजेंसी को सीधे तौर पर दोषी ठहराया था। ट्रम्प ने इसको दिए जाने वाले अमेरिका के अंशदान को ऐसे वक्त पर रोक दिया था जब वह सदी के सबसे बुरे वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल से जूझ रहा था। उन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन से अमेरिका की अंतिम वापसी की प्रक्रिया शुरू कर भी दी थी, लेकिन ऐसा होने से पहले, वे चुनाव हारकर सत्ता से बाहर हो गए थे। उनके बाद आए जो बाइडेन ने उक्त आदेश को उलट दिया और डब्ल्यूएचओ को अमेरिका का वित्तीय अंशदान बहाल कर दिया था। अब नए जारी किए गए कार्यकारी आदेश का मतलब है कि अमेरिका एक साल के भीतर संगठन को अपनी वित्तीय सहायता बंद कर देगा। वर्तमान में, डब्ल्यूएचओ के कुल वित्त पोषण में अमेरिका का अंशदान लगभग 18 फीसदी है। दो साल (2024 और 2025) के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन का बजट 6.8 बिलियन डॉलर है। डब्ल्यूएचओ का गठन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, स्वास्थ्य और बीमारियों के महत्वपूर्ण मामलों से निपटने के मंतव्य से एक विशेष संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के रूप में किया गया था। इसे वैज्ञानिकों, चिकित्सा विशेषज्ञों और स्वास्थ्य नीति निर्माताओं के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क युक्त एक तकनीकी एजेंसी के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया था। इसके मुख्य कार्यों में एक है नए पैदा हो रहे संक्रमणों पर निगरानी एवं सूचना साझा करना। दशकों से, इस एजेंसी के काम ने चेचक, यॉस, पीला बुखार, कुष्ठ रोग और पोलियो जैसी बीमारियों के उन्मूलन और नियंत्रण में मदद की है। यूएन एड्स नामक एक नई एजेंसी के माध्यम से इसकी एचआईवीध्एड्स पर की वैश्विक कार्रवाई भी उल्लेखनीय रही। अब, इसका ध्यान तपेदिक उन्मूलन पर है। वर्ष 2000 से नए संक्रमणों के उभरने और पुराने संक्रमण– जैसे कि सार्स, बर्ड फ्लू, एमईआरएस, इबोला, एमपॉक्स और कोविड 19 के लिए उभरने से एजेंसी का काम अधिक ध्यान खींच रहा है। एक वैश्वीकृत, एक–दूसरे से बहुत अधिक जुड़े एवं परस्पर निर्भरता वाले विश्व में, स्वास्थ्य सुरक्षा सीधे तौर पर अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ी हुई है। डब्ल्यूएचओ से हटने का फैसला वैश्विक समुदाय के अलावा खुद अमेरिका के लिए भी बुरा रहेगा। यह अमेरिका की दवा निर्माता कंपनियों को विश्व स्वास्थ्य संगठन के महामारी, इनफ्लुएंजा तंत्र से मिलने वाले रोग के प्रकोप और स्वास्थ्य आपात स्थिति संबंधी महत्वपूर्ण डेटा से वंचित कर देगा। यह निर्णय आगे वैश्विक महामारी संधि और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियमन जैसे अन्य तंत्रों में चल रही वार्ताओं से अमेरिका के हटने की राह खोलेगा। डब्ल्यूएचओ के साथ काम कर रहे दर्जनों अमेरिकी विशेषज्ञों को भी वापस बुलाकर अन्यत्र नियुक्त किया जाएगा। दो अमेरिकी संस्थान– सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ– महत्वपूर्ण मुद्दों पर डब्ल्यूएचओ के साथ काफी गहरे तक जुड़े हैं। ऐसी साझेदारियों का खत्म होना परस्पर हानिकारक रहेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए, अपने सबसे बड़े दानदाता का चले जाना एक गंभीर झटका है, वह भी ऐसे समय में जब अन्य देशों का योगदान पहले से ही कम होता जा रहा है। अमेरिका के बाद, अगला सबसे बड़ा दानदाता देश जर्मनी है, जिसका एजेंसी के वित्त पोषण में योगदान लगभग 3 प्रतिशत है। हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में, डब्ल्यूएचओ को कुछ गैर–राजकीय दानदाताओं से मिलने वाले धन में काफी वृद्धि हुई है। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन इस सूची में सबसे ऊपर है, उसके बाद नंबर आता है यूरोपियन आयोग और विश्व बैंक का। गेट्स फाउंडेशन पोलियो उन्मूलन और टीकों जैसे क्षेत्रों में काम में मदद कर रहा है।

अमेरिकी राष्ट्रपति से यूरोपीय संघ को सबसे ज्यादा नुकसान

नित्य

ट्रम्प की योरोप को खुली चुनौती का सामना करने के लिए, यूरोपियन आयोग(ईसी) अपने स्वयं के संसाधनों के आधार पर पुनरुद्धार के लिए अपना रोडमैप सामने लायेगा। इसी के सुधार कार्यक्रम में एक बचत और निवेश संघ की स्थापना करना शामिल है ताकि यूरोपीय संघ के परिवारों की 3000 लाख यूरो की नकदी जो सालाना महाद्वीप से बाहर जाती है, उसे घर पर निवेश किया जा सके। डोनाल्ड ट्रम्प के दूसरे कार्यकाल के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने और पदभार ग्रहण करने के पहले दिन उनकी नीतिगत घोषणाओं के एक सप्ताह के अन्दर उनका असर हर देश पर अलग–अलग पड़ा है, लेकिन यूरोपीय संघ के देशों, खासकर जर्मनी और फ्रांस में यह सबसे ज्यादा दहशत का विषय है। गत 23 जनवरी को यह प्रक्रिया और भी तेज हो गई, जब ट्रम्प ने डावोस में विश्व आर्थिक मंच के साथ बातचीत के दौरान अपनी नीतियों के बारे में विस्तार से बताया। यूरोपीय वर्चस्व वाले वर्ल्ड इकानामिक फोरम (डब्ल्यूईएफ) के सदस्य, जिन्होंने 20 जनवरी को अपना पांच दिवसीय वार्षिक सत्र शुरू किया था, 23 जनवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ वीडियो सत्र का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि सीईओ को अपने स्पष्टीकरणों पर अमेरिकी राष्ट्रपति से सीधे जवाब पाने का अवसर की उम्मीद थी। उन्हें वह अवसर मिल गया और बड़बड़ाहट के बीच, यूरोपीय सीईओ का मूड निराशा और मोहभंग का था। यूरोप पहले से ही अपने निराशाजनक आर्थिक दौर का सामना कर रहा है और ऐसा लगता है कि यह प्रक्रिया लंबी चलेगी। उन्होंने नाटो देशों से रक्षा खर्च को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 5 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए अपना आह्वान दोहराया। जब तक कि उन्होंने चुनौती नहीं दी थी, तब तक कई राष्ट्रों ने उनके पहले कार्यकाल के दौरान 2प्रतिशत जीडीपी लक्ष्य को भी पूरा नहीं किया था। ट्रम्प ने कहारू श्यह केवल 2प्रतिशत पर था और अधिकांश देशों ने मेरे आने तक भुगतान नहीं किया। मैंने जोर दिया कि वे भुगतान करें, और उन्होंने किया, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका वास्तव में उस समय अंतर का भुगतान कर रहा था। उन्होंने घोषणा की कि अमेरिका श्अन्य देशों से सम्मान की मांग करनाश शुरू करेगा, और उसके साथ ही उन्होंने केनेडा और यूरोपीय संघ का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि केनेडा अमेरिका का श्एक राज्यश बन सकता है, जो केनेडा के साथ अमेरिका के व्यापार घाटे को खत्म करने का एक तरीका है। श्हमें उनकी कारों की जरूरत नहीं है और हमें उनकी लकड़ी की भी जरूरत नहीं है।श यूरोपीय संघ के बारे में उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि ब्लॉक द्वारा अमेरिका के साथ श्बहुत, बहुत अनुचितश व्यवहार किया गया है। श्वे हमारे कृषि उत्पाद नहीं लेते हैं और वे हमारी कारें नहीं लेते हैं। फिर भी वे हमें लाखों की संख्या में कारें भेजते हैं,श उन्होंने कहा। उन्होंने सऊदी अरब और तेल उत्पादक कार्टेलओपेक से तेल की कीमतों में कटौती करने का आग्रह किया, और दावा किया कि इससे यूक्रेन में युद्ध समाप्त हो जायेगा। उन्होंने कहा, श्उन्हें यह बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। वास्तव में, कुछ हद तक, जो कुछ हो रहा है, उसके लिए वे बहुत जिम्मेदार हैं।श ट्रम्प के भाषण के बाद तेल की कीमतों में गिरावट आई। उन्होंने कहा कि अमेरिका को अपने ऊर्जा उत्पादन को दोगुना करने की जरूरत है, आंशिक रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने के लिए। ट्रम्प ने कहा कि वे नये बिजली संयंत्रों के लिए मंजूरी को तेज करेंगे, जिन्हें कंपनियां अपने संयंत्रों के बगल में लगा सकती हैं– ऐसा कुछ जो वर्तमान में नियमों के तहत संभव नहीं है। चिंताजनक रूप से, उन्होंने घोषणा की कि कंपनियां अपनी इच्छानुसार किसी भी चीज से इसे ईंधन दे सकेंगी, और बैकअप के रूप में कोयला, श्अच्छा, स्वच्छ कोयलाय रख सकेंगी। ट्रम्प की व्हाइट हाउस में वापसी ने पूरे यूरोप में आत्ममंथन की लहर पैदा कर दी है। उनके अमेरिका फर्स्ट सिद्धांत और यूरोपीय संघ के सामान पर टैरिफ की धमकी ने यूरोप के अभिजात वर्ग को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि वे अमेरिका के साथ बढ़ती आर्थिक खाई को कैसे पाट सकते हैं– और अतिरिक्त सैन्य व्यय के लिए आवश्यक अरबों का प्रबंध कैसे कर सकते हैं। डब्ल्यूईएफ पर यूरोपीय सीईओ का प्रभुत्व है। उनके अमेरिकी कंपनियों के साथ अच्छे संबंध हैं। उनमें से कई के पास यूरोपीय देशों में उत्पादन सुविधाएं हैं, जिससे नौकरियों का सृजन होता है और जीडीपी वृद्धि बढ़ती है। अब ट्रम्प ने डावोस बैठक में घोषणा की कि अमेरिकी कंपनियों से भी यूरोप में उनके उत्पादित सामान के अमेरिका को निर्यात के लिए शुल्क लिया जायेगा। उन्हें अमेरिका लौटने और अपने देश में सुविधाएं स्थापित करने के लिए कहा गया है। अगर ट्रम्प के इस उपाय को अंततरू यूरोप में गति मिलती है तो इसका मतलब यूरोपीय संघ के सदस्यों की पहले से ही अपंग अर्थव्यवस्थाओं को और अधिक झटका लगेगा। यूरोपीय आयोग के पास पहले से ही यूरोपीय सेंट्रल बैंक के पूर्व अध्यक्ष मारियोड्रेगी द्वारा तैयार की गयी एक रिपोर्ट है, जिसमें कहा गया है कि यूरोप में उत्पादकता श्बहुत कमजोरश है और गहन एकीकरण तथा समन्वित निवेश की तत्काल आवश्यकता है। 2025 के लिए संकेत पहले से ही चिंताजनक थे, लेकिन अब ट्रम्प की नीति घोषणाओं ने उभरते परिदृश्य को और खराब कर दिया है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2025 में यूरो क्षेत्र में एक प्रतिशत के मुकाबले अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए 2.7 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया है। जर्मनी की जीडीपी पिछले दो वर्षों से सिकुड़ रही है। स्थिति अनिश्चित है क्योंकि राष्ट्रीय चुनाव 23 फरवरी को होने वाले हैं। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि एक स्थिर गठबंधन बनेगा। डावोस में अनगिनत बातचीत में, व्यापारिक नेताओं और राजनेताओं ने यूरोपीय संघ के सामने आने वाली समस्याओं को उजागर कियारू फ्रांस और जर्मनी की मुख्य अर्थ व्यवस्थाओं में ठहराव और अमेरिकी तकनीकी दिग्गजों से प्रतिस्पर्धा करने में विफलता से लेकर लोक लुभावनवाद का उदय और यूक्रेन युद्ध तक। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुलावॉनडेरलेयेन ने फोरम में कहा कि श्पिछले 25 वर्षों में यूरोप ने अपने विकास को आगे बढ़ाने के लिए वैश्विक व्यापार के बढ़ते ज्वार पर भरोसा किया है। इसने रूस से सस्ती ऊर्जा पर भरोसा किया है और यूरोप ने अक्सर अपनी सुरक्षा को आउटसोर्स किया है। लेकिन वे दिन चले गये हैं।श डावोस में ट्रम्प के भाषण के बाद यह भावना घर कर गयी है कि यूरोप को ट्रम्प से खुद की रक्षा करनी होगी। पिछले दो साल से अमेरिका के संदर्भ में ऐसी चर्चा चल रही है, लेकिन यूरोपीय गर्वित हैं और उनके सीईओ अभी भी सोचते हैं कि उनके पास बदलाव लाने के लिए सबसे अच्छा दिमाग है, हालांकि ड्रैगी की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि यूरोपीय संघ की कंपनियां पिछले पचास वर्षों में एक भी 100 अरब यूरो की कंपनी नहीं बना पाई हैं, जबकि अमेरिका ने उस अवधि के दौरान 10 खरब यूरो से अधिक मूल्य की छह कंपनियां बनाई हैं।

मध्यम वर्ग की क्रय शक्तिबढ़ाएगी खपत

डॉ. जयंतीलाल

इन दिनों पूरे देश के साथ–साथ मध्यम वर्ग की निगाहें वित्तमंत्री द्वारा एक फरवरी को प्रस्तुत किए जाने वाले केंद्रीय बजट 2025–26 की ओर लगी हुई हैं। दरअसल, देश के विकास का इंजन कहे जाने वाले मध्यम वर्ग की मुट्ठियों में धन की कमी के कारण उनके निजी उपभोग पर होने वाले खर्च में गिरावट से विकास दर प्रभावित हो रही है। उम्मीद है कि वित्तमंत्री आगामी बजट में टैक्स में कटौती और वित्तीय प्रोत्साहनों से आयकरदाता और मध्यम वर्ग की क्रयशक्ति बढ़ाकर मांग में वृद्धि करके अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाएंगी।

कयास लगाए जा रहे हैं कि वित्तमंत्री नए टैक्स रिजीम के तहत 10 लाख रुपये तक की कमाई को टैक्स फ्री कर सकती हैं। इससे मध्यम वर्ग के हाथ में जो अतिरिक्त धनराशि बचेगी, उससे खपत बढ़ाने में बड़ी मदद मिलेगी।

वस्तुतः मध्यम वर्ग के खर्च और निजी उपभोग का देश की विकास दर की रफ्तार से सीधा संबंध है। कोरोना–19 के बाद से मध्यम वर्ग के पास अपने उपभोग खर्च के बाद निवेश के लिए खर्च में लगातार कमी आ रही है। मध्यम वर्ग की जीवनशैली को बनाए रखने की लागत में अत्यधिक तेज वृद्धि ने इस वर्ग की वित्तीय मजबूती कम की है। बढ़ती हुई, खुदरा महंगाई ने भी मध्यम वर्ग के परिवारों पर वित्तीय दबाव को बढ़ा दिया है। पिछले वर्ष 2024 में खाद्य पदार्थों की खुदरा महंगाई रिजर्व बैंक के निर्धारित मानक से अधिक रही है। स्थिति यह है कि निजी उपभोग में कमी ने निजी पूंजीगत व्यय के चक्र की रफ्तार घटा दी है। कोविड–19 के बाद मध्यम वर्ग की कमाई की रफ्तार में कमी आई है। साथ ही बढ़ती वित्तीय देनदारी और कर्ज की किस्त अदायगी का बोझ बढ़ने से मध्यम वर्ग चिंतित है। निरूसंदेह, सरकार ने विगत वर्षों में जहां गरीब लोगों के लिए ढेर सारी राहतों का ऐलान किया, वहीं कॉर्पोरेट जगत पर भी सरकार ने ध्यान दिया। लेकिन सबसे अधिक टैक्स देने वाला मध्यम वर्ग पीछे छूट गया। पिछले विभिन्न बजटों में मध्यम वर्ग की चिंताओं पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। इस वर्ग पर लगाए गए कर की तुलना में इस वर्ग को सार्वजनिक सेवाओं के जरिए बहुत कम रिटर्न मिला है, ऐसे में यह अपेक्षा की जा रही है कि आगामी बजट सरकार के लिए लक्षित कर सुधारों को आगे बढ़ाने, शहरी उपभोग मांग को बढ़ाने और मध्यम वर्ग को सीधे लाभ पहुंचाने वाली सेवाओं को बढ़ाने वाला बजट होगा। उपयुक्त कर राहत से एक अच्छा आर्थिक चक्र बन सकता है। निस्संदेह, मध्यम वर्ग पर कर का बोझ कम करने से खपत बढ़ेगी। इससे जीएसटी संग्रह में वृद्धि होगी और कर योग्य आय वालों का आधार बढ़ेगा। उल्लेखनीय है कि पिछले 10 वर्षों में लगातार आयकर रिटर्न भरने वाले आयकरदाताओं की संख्या और आयकर की प्राप्ति में छलांगें लगाकर वृद्धि हुई है। चालू वित्त वर्ष 2024–25 में अप्रैल से दिसंबर, 2024 तक आयकर सहित प्रत्यक्ष कर संग्रहण करीब 16 लाख करोड़ रुपये रहा है, जो कि पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 16 फीसदी से भी ज्यादा है। इस परिप्रेक्ष्य में आईसीआरए की रिपोर्ट कहती है कि आगामी बजट में सरकार व्यक्तिगत आयकरदाताओं को राहत दे सकती है, इससे कर संग्रह पर असर पड़ने का खतरा नहीं है। वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान प्रत्यक्ष कर संग्रह में 12 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है। इस अनुमान का आधार आय और कॉर्पोरेट कर राजस्व में इजाफा होना है। अप्रत्यक्ष करों में 9 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है। जीएसटी संग्रह में 10.5 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है। सीमा शुल्क में भी 5 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है। ऐसे में मध्यम वर्ग के लिए टैक्स में कटौती और टैक्स ढांचे को आसान बनाकर खर्चों और सेविंग्स को बढ़ाने की कोशिश इस बजट में दिखाई दे सकती है। खासतौर से वेतनभोगी वर्ग को लाभान्वित करने के भी विशेष प्रावधान नए बजट में दिखाई दे सकते हैं। नई टैक्स रिजीम के तहत आयकर स्लैब में और बदलाव हो सकता है, ताकि अधिक से अधिक करदाता इसे अपनाने के लिए प्रेरित हो सकें। 30 प्रतिशत की दर को 20 लाख रुपये से अधिक की आय वालों पर लागू किया जाना अत्यधिक लाभप्रद होगा। नए बजट के तहत आयकर से संबंधित पुराने टैक्स रिजीम के अंतर्गत धारा 80सी के तहत छूट बढ़ाई जा सकती है। नए बजट 2025–26 में पुराने टैक्स रिजीम के तहत भी स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट बढ़ाई जा सकती है। अभी पुरानी व्यवस्था में नौकरीपेशा लोगों और पेंशनधारकों को 50,000 रुपये तक की छूट दी जाती है। नई टैक्स रिजीम के तहत 75,000 रुपये की कटौती का लाभ मिलता है। वहीं दूसरी ओर अभी आयकर के कर दायरे में इजाफा किए जाने की बड़ी संभावनाएं हैं। बड़ी संख्या में उद्योग–कारोबार सेक्टर में कार्यरत रहते हुए कमाई करने वाले, महंगी आरामदायक व विलासिता की वस्तुओं का उपयोग करने वाले तथा पर्यटन के लिए विदेश यात्राएं करने वालों में से भी बड़ी संख्या में लोग या तो आयकर न देने का प्रयास करते हैं या फिर बहुत कम आयकर देते हैं। स्थिति यह है कि वर्ष 2023–24 में देश के 140 करोड़ से अधिक लोगों में से सिर्फ 8.09 करोड़ लोगों ने आयकर रिटर्न दाखिल किए। इनमें से भी 4.90 करोड़ लोगों ने शून्य कर योग्य आय की सूचना दी। सिर्फ 3.19 करोड़ लोगों ने ही आयकर दिया है। ऐसे में देश के सकल घरेलू उत्पाद में आयकर का योगदान बहुत कम बना हुआ है। वित्तमंत्री आयकर सुधारों के तहत वर्ष 2025–26 के बजट सत्र में नया आयकर कानून पेश कर सकती हैं। इसका मकसद मौजूदा इनकम टैक्स एक्ट 1961 को आसान, स्पष्ट और समझने योग्य बनाना है। इसके तहत अनावश्यक और अप्रचलित प्रावधानों को हटाया जाएगा। कर विवादों को कम किया जाएगा। टैक्सपेयर्स के लिए अनुपालन को आसान बनाया जाएगा।

मानव सेवा ही परम धर्म है : डॉ गोरखनाथ पटेल

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। जिलाधिकारी दिनेश चंद्र सिंह के आह्वान पर बीएसए डॉक्टर गोरखनाथ पटेल के नेतृत्व में बेसिक शिक्षा की पूरी टीम ने श्रद्धालुओं की सेवा का कार्य पूरी तन्मयता से किया।प्रयागराज महाकुंभ में जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए सतहरिया पड़ाव पर पूर्ण व्यवस्था की गई थी।उनके भोजन,आवास,दवा आदि की पूरी व्यवस्था की गई जिससे उन्हें किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े।श्रद्धालुओं के लिए यात्रा की थकान को दूर करने के लिए स्वयं बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ गोरखनाथ पटेल द्वारा सुन्दरकाण्ड पढ़ा गया।बीएसए डॉ गोरखनाथ पटेल ने प्रयागराज महाकुंभ में जाने वाले श्रद्धालुओं का सत हरिया पड़ाव पर उनकी सेवा करने के लिए,उनके खान–पान की व्यवस्था करने के लिए और जगह–जगह जनपद जौनपुर में सभी बेसिक शिक्षा के जितने विद्यालय थे वहां पर श्रद्धालुओं के भोजन की व्यवस्था,उनके रोकने स्थान करने की दैनिक कार्यक्रम करने की व्यवस्था करने के लिए,आवागमन की सुविधा को सुपर बनाए रखने के लिए समस्त टीम, शिक्षक संगठनों के सभी पदाधिकारी गण,बेसिक शिक्षा विभाग के सभी खंड शिक्षा अधिकारी गण,बेसिक शिक्षा परिवार की समस्त टीम का मुखिया होने के नाते हृदय से आभार व्यक्त किया।सभी लोगों ने श्रद्धालुओं की सेवा पूरी तन्मयता से की।डॉगोरखनाथ पटेल ने कहा कि निस्वार्थ सेवा भाव से की गई सेवा सच्ची और सार्थक होती है।उन्होंने कहा कि श्रद्धा से ज्ञान, विनम्रता से मान और योग्यता से स्थान मिलता है, जिन लोगों के पास ये तीनों होते हैं, उन्हें हर जगह मान–सम्मान मिलता है समय कैसा भी हो, अच्छा हो या बुरा, हमें धैर्य और विनम्रता नहीं छोड़नी चाहिए।

हैदरगंज, सीहीपुर में ग्राम प्रधान व ग्राम वासियों के सहयोग से विशाल भंडारे का आयोजन

(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या।महाकुंभ प्रयाग से हैदरगंज तारुन होते हुए दर्शन नगर के रास्ते अयोध्या रामलला के दर्शन करने जाते हुए श्रद्धालुओं के लिए हैदरगंज क्षेत्र में दर्जनों स्थानों पर भंडारे की व्यवस्था की गई है।क्षेत्र के सीहीपुर में ग्राम वासियों व ग्राम प्रधान के सहयोग से विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है।ग्राम प्रधान प्रतिनिधि राम प्रकाश यादव ने बताया कि कम्पोजिट विद्यालय सीहीपुर के प्रांगण में परम पूज्य संत श्री नारायणाचार्य जी के आवास के सामने महाकुंभ प्रयाग से चलकर आने वाले श्रद्धालुओ के लिए विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है जो की लगातार 2 दिन से चल रहा है और अभी आगे चलता भी रहेगा।इस मौके पर प्रधान प्रतिनिधि राम प्रकाश यादव के अलावा अतुल मिश्रा, अभय मिश्रा, अमोल मिश्रा ,अवधेश गोस्वामी, राम नारायण गोस्वामी, ऋषि सिंह ,सुभाष सिंह, रोशन सिंह, गुड्डू पूर्व प्रधान, संजय मिश्रा, निलेश मिश्रा, अजय मिश्रा, मुकेश मिश्रा, आदर्श मिश्रा, विष्णु मिश्रा, अंकित मिश्रा, पप्पू मिश्रा, राजेंद्र मिश्रा, कृष्ण चंद्र मिश्रा, रमेश मिश्रा, सुरेंद्र नाथ मिश्रा, दिलीप गोस्वामी, राम नेवल मिश्रा, वीरेंद्र नाथ मिश्रा, ध्रुव गोस्वामी सैकड़ो लोग श्रद्धालुओं की सेवा में उपस्थित रहे।इसी क्रम में बेला, हैदरगंज, सहित ग्राम प्रधान के सहयोग से दर्जनों स्थानों पर लगातार भंडारा चल रहा है।

महाकुंभ से अयोध्या आ रहे श्रद्धालुओं के स्वागत में जाना बाजार व आसपास तीसरे दिन भी जुटे कई समाजसेवी

(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या।महाकुम्भ प्रयागराज से अयोध्या आ रहे श्रद्धालुओ का तीसरे दिन भी जमकर जगह–जगह स्वागत हो रहा है।श्रद्धालुओं का स्वागत करने के लिए क्षेत्रवासियों की भीड़ उमड रही है।जिससे बाजारों में भंडारा स्थलों पर पुलिस के जवान भी भीड़ नियंत्रित करने में जुटना पड रहा हैं।वही श्रद्धालु भी अपने सेवा से पूरी तरह अभिभूत नजर आ रहे हैं।थाना क्षेत्र हैदरगंज के बेलारामबाग ,सीहीपुर, हनुमानगढ़ी चौराहा, धोवीना चौराहा, ब्रह्म बाबा,खपराडीह, जाना बाजार आदि स्थानों पर आज भी भोजन ठहराव की व्यवस्था में सैकड़ो समाजसेवी जुटे हैं। श्रद्धालुओं को जलपान भोजन के साथ राति रूकने की पूरी व्यवस्था देने में जुटे गरौली के प्रधान राज नारायण जायसवाल, पूर्व प्रधान अन्जय , जिला पंचायत सदस्य रहे सियाराम सर्राफ, मोनू गुप्ता, राजू मौर्य, अनिल जायसवाल, शिवम ,वेद गुप्ता, जगपाल अंकुर मोदनवाल ,सुमित, अंकित ,आयुष ,सचिन ,रमेश ,राकेश गुप्त, महेंद्र ,सरजू ,प्रदीप यादव ,अमित यादव, भगनलाल ,सिंटू ,पप्पू, धीरज, प्रधान राकेश अग्रहरी ,अजय कुमार यादव, आर के टी पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य इन्द्रदेव त्रिपाठी,गंगाराम निषाद, राकेश जायसवाल आदि युवाओं की टीम कर्नाटक ,उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश ,वेस्ट बंगाल से कुंभ आए श्रद्धालु जो अपने निजी वाहनों से अयोध्या जा रहे हैं।उन्हें रोक रोक कर जलपान नाश्ता भोजन के साथ ठहराव की व्यवस्था देने में लगे हैं।भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जगह जगह चौराहे पर हैदरगंज थाने की पुलिस कर्मी, दरोगा लक्ष्मीकांत तिवारी,श्रीपद मौर्य कांस्टेबल क यादव कुलदीप दीपक आदि महिला पुरुष आरक्षित मौजूद रहे ।

व्यापार को बढ़ाने के लिए सरकार ने दी कई महत्वपूर्ण योजनाएं : रविन्द्र जायसवाल

(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या।गुरुवार को भाजपा ने इनायतनगर स्थित आस्कर केरला पब्लिक स्कूल में व्यापारी सम्मेलन का आयोजन किया।अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता के संयोजन में

आयोजित सम्मेलन के मुख्य अतिथि स्टांप न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार रविन्द्र जायसवाल ने कहा कि व्यापारी अपना पैसा लगाकर व्यापार करता है, और सरकार को टैक्स देता है।टैक्स से सरकार की आमदनी होती है। यह सड़क, अस्पताल बनाने व अनाज बांटने के काम में आती है।व्यापारी बिना तनख्वाह के काम करके सरकार को टैक्स देता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री ने व्यापार को बढ़ाने के लिए कई योजनाएं दी है। अगर अयोध्या में कोई होटल खोलना हो तो स्टाम्प में छूट मिलेगी। इसके साथ में अनुदान भी मिलेगा। युवाओं को पांच लाख का लोन चार साल के लिए बिना व्याज के मिल रहा है। जिसमें दस प्रतिशत सब्सिडी होगी। अगर व्यापार बढ़ेगा तो लोगो को रोजगार मिलेगा।जिले के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि कानून व्यवस्था बेहतर हो तो व्यापार बढ़ता है। 2017 के पहले सपाई नारा लगाते थे कि जो जमीन खाली है वह जमीन हमारी है। गाजियाबाद से गोरखपुर तक गुंडे वसूली करते थे। लेकिन प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद किसी गुंडे की हिम्मत नहीं है कि वह व्यापारियों का शोषण कर ले, वसूली कर ले, जमीन कब्जा कर ले।उन्होंने कहा कि सरकार ने व्यापारियों के लिए कई योजनाएं चलाई हैं। मुद्रा योजना के माध्यम से ठेला, पटरी दुकानदारों को लाभ दिया गया है। सरकार निरंतर व्यापारियों की उन्नति के लिए कार्य कर रही हैं। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद यहां के व्यापारियों का व्यापार कई गुना बढ़ा है। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो व्यापारी परिवार से आते हैं उन्होंने बचपन में स्टेशन पर चाय बेचने का व्यवसाय किया। भाजपा नेता व पूर्व राज्यसभा सांसद विनय कटियार ने कहा कि मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर मिले निर्देशों का शत प्रतिशत पालन पार्टी के कार्यकर्ता करे। सबका साथ सबका विकास के पथ पर चलते हुए हम सबका विश्वास हासिल करने के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के दिया गया है। सभा स्थल पर पहुंचने के बाद मुख्य अतिथि को 51 किलो की माला पहनाकर स्वागत किया गया। भाजपा प्रत्याशी चन्द्रभानु पासवान ने सभी का अभिवादन किया। मौके पर जिलाध्यक्ष संजीव सिंह, पूर्व विधायक टाण्डा संजू देवी, नगर पंचायत अध्यक्ष गोसाईगंज विजय लक्ष्मी जायसवाल, व्यापारी नेता चन्द्र प्रकाश गुप्ता, अमल गुप्ता, केन्द्रीय दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष मनोज जायसवाल, अरुण गुप्ता, अशोक कसौधन, रामसजीवन मिश्रा, रघुनंदन चौरसिया, बैजनाथ वैश्य, संतोष जायसवाल, जर्नादन मौर्या, अजीत यादव मौजूद रहे।

अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन के अंदर बाहर चप्पे चप्पे पर रही सुरक्षा कर्मियों की तैनाती

(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या। गुरुवार को भी महाकुंभ प्रयागराज से रामनगरी आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कठिनाइयों का सामना न करना पड़े इसके लिए रेलवे विभाग पूरी तरीके से सक्रिय दिखाई दिए।बताते चले की मौनी अमावस्या को प्रयागराज में भगदड़ के चलते वहां पर जाने वाले लोगों को अगले आदेश तक प्रशासन ने प्रतिबंधित कर दिया है। जिसके चलते आशंका यही जताई जा रही थी कि वह भीड़ अब अयोध्या की ओर टूटेगी।बुधवार की देर शाम से लेकर गुरुवार को भी भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ रेल, बस वह अन्य निजी वाहनों से रामनगरी की ओर आई हुई दिखाई दी। सबसे ज्यादा भीड़ बुधवार की देर शाम पैदल चलने वालों की दिखाई दे रही थी जो गुरुवार तक बनी रही। रामनगरी जा रहे कुछ श्रद्धालुओं ने बताया कि पहले तो वह प्रयागराज जा रहे थे लेकिन जब उनको पुलिस कर्मियों द्वारा रोका गया तो वे अब सबसे पहले राम जन्मभूमि जाकर रामलला का दर्शन करेंगे फिर उसके बाद प्रयागराज जाएंगे। जिसके चलते एक बार फिर रामनगरी में भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। इस दौरान किसी भी तरीके की इस श्रद्धालुओं को कठिनाइयों का सामना न करना पड़े इसके लिए रेलवे प्रशासन ने अयोध्या कैंट व अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर पर्याप्त संख्या में राजकीय रेलवे सुरक्षा बल तथा केन्द्रीय रेलवे रेलवे पुलिस बल की तैनाती की गई थी। जो इन रेलवे स्टेशनों पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं की बारीकी से जांच कर उनकी मदद करते हुए नजर आए तथा यहां तक कि उन्हें उनकी ट्रेनों तक पहुंचाने का भी सराहनीय कार्य किया। इस दौरान अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पर मुख्य अग्निशमन अधिकारी एमपी सिंह के दिशा निर्देश पर किसी भी अप्रिय घटना से तुरंत निपटने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियों कीभी तैनाती की गई थी। जहां पर फायर विभाग के कर्मी हृदयनाथ विश्वकर्मा शाहिद अन्य फायर कर्मी मौजूद रहे। इस मौके पर वहां पर तैनात अधिकारियों ने बताया की सुरक्षा की दृष्टि के साथ ही साथ श्रद्धालुओं को किसी तरीके की परेशानी ना हो इसके लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। वही अराजक तत्वों पर पहनी नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से बने हुए नियंत्रण कक्ष से वहां पर तैनात सुरक्षा कर्मियों द्वारा निगरानी की जा रही है।इसके लिए पर्याप्त संख्या में सादे पोशाक में मैं भी सुरक्षा कर्मियों के साथ साथ खुफिया तंत्र भी सक्रिय है। जो वहां पर हर एक गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं।

समस्त टीवी संभावित बच्चों की नियमित जांच अत्यंत आवश्यक : सीएमओ

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर । मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत सहयोगी संस्था वर्ल्ड हेल्थ पार्टनर के सहयोग से जनपद की राजकीय एवं निजी चिकित्सालाओं के नर्सिंग स्टाफ के लिए बोल क्षय रोगियों के उचित उपचार एवं नियमित जांच के संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के संरक्षण में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ लक्ष्मी सिंह ने कहा कि समस्त टीवी संभावित बच्चों की जांच अत्यंत आवश्यक है बाल क्षय रोगियों की समय पर पहचान और उपचार से हम क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लक्ष्य की प्राप्ति में सहयोग कर सकते हैं जिला छय रोग अधिकारी डॉक्टर राकेश सिंह ने नर्सिंग स्टाफ से अपील करते हुए कहा कि टीवी उन्मूलन के लिए न केवल स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं बल्कि जन भागीदारी भी अत्यंत महत्वपूर्ण है बच्चे अक्सर अपनी परेशानी व्यक्त नहीं कर पाते , जिसके कारण उन में टीवी की पहचान में देरी हो जाती है अतः नर्सिंग स्टाफ को बाल टीवी के लक्षणों के प्रति जागरूक और संवेदनशील रहना चाहिए कार्यशाला में राज्य इकाई से लक्ष्मी सिंह ने नर्सिंग स्टाफ को प्रशिक्षण प्रदान किया तथा नर्सिंग स्टाफ के सवालों के जवाब भी दिए कार्यशाला के संचालन का उत्तरदायित्व रोहित कुमार जिला प्रोजेक्ट मैनेजर तथा नंदकिशोर शर्मा जिला प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर तथा वीरेंद्र सिंह जिला प्रोजेक्ट कॉर्डिनेटर और जिला नर्स मेंटर रूबी सिंह ने संभाला ! कार्यक्रम के दौरान छोटे बच्चों में टीवी की पहचान के लिए गैस्ट्रिक एस्पिरेट प्रक्रिया का लाइव प्रदर्शन लक्ष्मी सिंह स्टेट नर्स मेंटर के द्वारा किया गया इस प्रदर्शन ने नर्सिंग स्टाफ को बाल छह रोगियों के शीघ्र पहचान, उपचार और सटीक जांच इस तथा गैस्ट्रिक प्रक्रिया तथा बाल टीवी के लक्षणों के प्रति जागरूक बनाना था कार्यशाला में उपस्थित सभी नर्सिंग स्टाफ ने इसे अत्यंत उपयोगी बताया ताया और टीवी उन्मूलन के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की! NTEP स्टाफ से डीपीसी सलिल यादव सर ने 100 कंले कैंपिंग के बारे में बताया तथा#WOV#सुशील अग्रहारी सर तथा राजीव श्रीवास्तव सर ने नेट टेस्टिंग तथा#VSXWXP सैंपल कलेक्शन के बारे में जानकारी दी

असुरन-पिपराइच मार्ग चैड़ीकरण के पुनरीक्षित प्रस्ताव को मिली मंजूरी

गोरखपुर, (संवाददाता)। असुरन चौक से पिपराइच तक करीब 19.5 किलोमीटर लंबी सड़क को फोरलेन बनाने को लेकर संशोधित प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। चौड़ीकरण की जद में आ रहे मकान, दुकान व जमीनों का मुआवजा वितरण फरवरी में शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही निर्माण भी शुरू हो जाएगा। कुशीनगर और महराजगंज जिले से जुड़ी असुरन–पिपराइच मार्ग पर वाहनों का दबाव अधिक है। इस रोड के किनारे नई–नई कॉलोनियां भी विकसित हो रही हैं। जंगल धूसड़ तक कई नए मोहल्ले बस गए हैं। इसे देखते हुए पिछले साल इस सड़क को फोरलेन बनाने की मंजूरी मिली थी। पहले यह सड़क असुरन से लेकर पिपराइच तक 29 मीटर चौड़ी बननी थी। लेकिन असुरन के व्यापारियों की परेशानी को देखते हुए मुख्यमंत्री के निर्देश पर सड़क की चौड़ाई आबादी के बीच घटाकर 20.5 मीटर कर दी गई। चौड़ाई कम करने से तमाम लोगों की मकान–दुकान टूटने से बच जाएंगे। इसके बाद पिपराइच के लोग भी कस्बे में सड़क की चौड़ाई कम करने की मांग करने लगे। कस्बे के मकानों को बचाने के लिए फोरलेन बाईपास बनाने की संभावना भी तलाशी गई, लेकिन उपयुक्त जगह नहीं मिली। इसके बाद इसी सड़क को कप्तानगंज जाने वाली सड़क तक 20.5 मीटर चौड़ा करने का प्रस्ताव बनाया गया। नई डिजाइन में दोनों लेन की चौड़ाई 7–7 मीटर रहेगी। शेष पर डिवाइडर, फुटपाथ और नाला का निर्माण किया जाएगा। आबादी के बीच चौड़ाई घटने से बहुत से व्यापारियों का मकान और दुकान टूटने से बच जाएगा। साथ ही इससे निर्माण की लागत में भी कमी आएगी। पीडब्ल्यूडी निर्माण खंड तृतीय को इस सड़क के निर्माण की जिम्मेदारी मिली है। नए प्रस्ताव के अनुरूप जमीन के सीमांकन के साथ ही असुरन से लेकर पिपराइच तक सड़क की पैमाइश का काम भी पूरा हो गया है। कहां कितने मकान टूटेंगे और कितनी जमीन का अधिग्रहण होगी, ये सारी गणना हो चुकी है। इसके अनुरूप ही संशोधित प्रस्ताव भेजा गया है। संशोधित प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है, लेकिन अभी उसकी कॉपी मुख्यालय से प्राप्त नहीं हुई है। कॉपी मिलने पर ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि किस जगह पर कितना मुआवजा वितरण करना है। प्रयास है कि फरवरी में मुआवजा वितरण कर निर्माण कार्य आरंभ करा दिया जाए।

श्रद्धालुओं को भोजन कराकर अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पर संचालित रेलवे केंटीन के प्रो बी एन सिंह चौहान ने किया सराहनीय कार्य

पी पी साइज

अयोध्या।इस समय रामनगरी में लाखों की संख्या में प्रभु श्री राम की एक झलक पाने के लिए लोग आतुर हैं। जो प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ मेले से भारी संख्या में अयोध्या आ रहे हैं।हालात इस कदर यहां पर भीड़ की हो गई है कि जिला प्रशासन को पूरा बाजार तथा बीकापुर मैं हॉल क्षेत्र घोषित करना पड़ा। इसके बावजूद भी जिले में श्रद्धालुओं का आवाजाही बना हुआ है। जिसके चलते यहां पर होटल या गेस्ट हाउस की छोड़िए श्रद्धा ल खुले आसमान में रहने को मजबूर हैं। इनकी मदद करने के लिए जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन के अलावा कुछ समाजसेवी संस्थान भी आगे बढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। कुछ लोग उनका रहने के लिए आवाज दे रहे हैं तो कुछ लोग उनका भोजन करने के लिए भंडारा भी कर रहे हैं। ऐसा ही सराहनीय कार्य अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पर संचालित केंटीन शिव

एंड संस के प्रोपराइटर बी एन सिंह चौहान ने बुधवार की देर रात 50 से अधिक श्रद्धालुओं को भोजन कराकर किया। उन्होंने बताया कि देर रात करीब 11रू12 बजे के आसपास राजस्थान प्रांत से आए लगभग चार दर्जन से अधिक श्रद्धालु भोजन के लिए भटक रहे थे। जब वे सभी इसे भोजन के लिए रेस्टोरेंट तथा होटल का पता पर पूछा तो इन्होंने कहा इस समय भोजन की कोई व्यवस्था आसपास नहीं है। इस पर जब यह श्रद्धालु हताश होकर जाने लगे तो इन्होंने अपने कर्मियों को तुरंत बुलाकर इन सभी श्रद्धालुओं के लिए भोजन का प्रबंध कराया।देर रात में इन सभी लोगों को भोजन उन्होंने भोजन कराया। उनको उनके द्वारा किए गए इस सराहनीय कार्य की की चर्चा आज पूरे अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पर थी। इस संबंध में जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने कहा कि परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है।

राजकीय पुस्तकालय मे गांधी जी के पुण्य तिथि पर मनाया गया एंटी लेप्रोसिटी

अयोध्या।गुरुवार को राजकीय पुस्तकालय में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करके एंटी लेप्रोसिटी के रूप में मनाया गया।इस मौके पर प्रभारी पुस्तकालय डॉक्टर अवनीश कुमार पांडे सह जिला विद्यालय निरीक्षक ने पाठकों को शपथ दिलाई कि कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्तियों को चिन्हित करके उनकी स्वच्छता की व्यवस्था कराएंगे।उन्हें जागरूक कर कुष्ठ रोग का इलाज संभव है।ऐसे लोगों को छुआछूत अथवा अन्य दृष्टि ना देखें क्योंकि यह रोग है जो ठीक किया जा सकता है।इस मौके पर वित्त एवं लेखाअधिकारी अनुपम कुमार ने बताया कि वें अपने

स्तर से पांच कुष्ठ रोगियों को गोद लेता हूं उनकी समस्त व्यवस्था की देखभाल करूंगा स्काउट मुख्यालय आयुक्त जिला मंत्री आलोक तिवारी ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की अभाव में लोगों को पता ही नहीं चलता कि वह कुष्ठ रोग से पीड़ित है।समाज के डर से किसी से चर्चा भी नहीं करते ऐसे लोगों को बच्चों के माध्यम से चिन्हित कराकर दवा की व्यवस्था की जाएगी जल्द ही गांव में जाकर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा कार्यक्रम में अनूप पांडे सत्य प्रकाश सुषमा मिश्रा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।

अडानी गैस प्राइवेट लिमिटेड ध्रुव गंगा एसोसिएट्स CNG स्टेशन पर संयुक्त स्तर–3 मॉक ड्रिल का आयोजन

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर । सीएनजी गैस एजेंसी पर गैस लेने के दौरान एजेंसी पर हुए कोई अचानक आग लग जाने पर किस पर उसे तुरंत रोक जाय इसको लेकर आज इंडियन ऑयल – अडानी गैस प्राइवेट लिमिटेड ध्रुव गंगा एसोसिएट्स CNG स्टेशन पर संयुक्त स्तर–3 मॉक ड्रिल का सफल आयोजन किया गया। यह अभ्यास अभय गिरी GA हेड नागेंद्र कुमार द्विवेदी फायर सेफ्टी ऑफिसर, एम. के. तिवारी (गेल इंडिया लिमिटेड), एवं रमेश प्रजापति (टोरेंट गैस लिमिटेड) के मार्गदर्शन एवं सहयोग से संपन्न हुआ। मॉक ड्रिल के दौरान CNG स्टेशन की स्टील पाइपलाइन में भारी गैस रिसाव और आग लगने की स्थिति को दर्शाया गया। प्।ळच्स् टीम ने

समन्वित प्रयासों से स्थिति को सफलतापूर्वक नियंत्रित किया, जिससे आपातकालीन प्रतिक्रिया एवं सुरक्षा तैयारी का उत्कृष्ट प्रदर्शन हुआ। इस अभ्यास में प्रमुख रूप से सर्वेश उपाध्याय, सिद्धांत जायसवाल, शशांक दुबे, नागेश मौर्य, असद ताहिर, प्रणव श्रीवास्तव, रामलाल जायसवाल, अमृत राज सहित अन्य टीम सदस्य शामिल रहे। मॉक ड्रिल सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन संचालन में सुरक्षा एवं आपातकालीन तैयारी के प्रति IOAGPL की प्रतिबद्धता को और मजबूत करने का प्रमाण है।

जिलाधिकारी ने श्रद्धालुओं के लिए की गयी व्यवस्थाओं का किया निरीक्षण

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। जिलाधिकारी डा0 दिनेश चन्द्र के द्वारा जौनपुर–प्रयागराज सीमा मुंगराबादशाहपुर के सतहरिया में प्रयागराज महाकुम्भ में जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए की गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी द्वारा श्रद्धालुओं के लिए की गई खाने की व्यवस्था सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता तथा यातायात व्यवस्था देखी गयी। इस दौरान जिलाधिकारी ने महाकुंभ के दौरान इस व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की साथ ही कहा कि इस सेवा कार्य में जिला प्रशासन के साथ स्वयं सेवी संस्थाएं भी जुड़ी हुई है। उन्होंने निर्देशित किया कि श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्नान कराने तथा यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित रहे इसके लिए पुलिस प्रशासन के लोग सक्रिय रहे। इस दौरान जिलाधिकारी द्वारा स्वास्थ्य शिविर का भी निरीक्षण किया गया। मछलीशहर बस अड्डे पर श्रद्धालुओं के लिए बनाये गये ठहराव स्थल के निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी के द्वारा श्रद्धालुओं को सूक्ष्म जलपान, बिस्कुट इत्यादि भी वितरित किया गया। इस अवसर पर ज्वांइट मजिस्ट्रेट सौरभ कुमार, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डा0 गोरखनाथ पटेल, जिला पंचायत राज अधिकारी नत्थुलाल गंगवार सहित अन्य उपस्थित रहे।

मेला प्रशासन के निर्देशों का पालन करें, अफवाहों पर ध्यान न देंश, सीएम योगी की श्रद्धालुओं से अपील

लखनऊ, (संवाददाता)। महाकुंभ में हुई भगदड़ के बाद मुख्यमंत्री योगी ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वह संगम नोज जाने के बजाय निकट के घाट पर स्नान कर लें। सीएम योगी ने कहा है कि स्नान के लिए कई घाट बनाए गए हैं। लोग वहां स्नान कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में प्रशासन के नियमों का ध्यान रखें और किसी प्रकार की अफवाह में न आएं। मौनी अमावस्या पर भारी भीड़ और भगदड़ की घटना के चलते सभी अखाड़ों ने अमृत स्नान न करने का एलान किया है। यह एलान अखाड़ा परिषद अध्यक्ष श्रीमहंत रविंद्र गिरी ने निरंजन छावनी से किया। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष ने कहा जिस तरह से श्रद्धालुओं की भीड़ है और भगदड़ की घटना सामने आई है उससे अखाड़े ने स्नान न करने का फैसला लिया है। अखाड़े के वहां जाने से स्थिति और भी बिगड़ सकती थी।

संयम बरतने की अपील

मौके से सामने आए वीडियो के अनुसार कुछ महिलाओं और बच्चों को भी चोट लगी है। अभी हालात काबू में बताये जाते हैं। महाकुंभ नगर प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अफवाहों पर ध्यान न देने और संयम बरतने की अपील की है। बताया जाता है कि प्रयागराज के संगम तट पर अमृत स्नान से पहले देर रात करीब 2 बजे भगदड़ मच गई। इसमें कुछ लोगों के मरने की बात कही जा रही है। एक प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक भगदड़ मचते ही लोग दौड़ने लगे। अभी प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा है कि श्रद्धालुगण मां गंगा के जिस भी घाट के समीप हैं, वहीं स्नान करें, संगम नोज की ओर जाने का प्रयास न करें। स्नानार्थियों के लिए कई घाट बनाए गये हैं, जहां सुविधाजनक रूप से स्नान किया जा सकता है। उन्होंने सभी से मेला प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। सीएम योगी ने सभी से

अपील की है कि वह किसी भी प्रकार के अफवाहों पर ध्यान न दें।

संगम में स्नान का आग्रह छोड़ दें

सीएम योगी के साथ ही धर्म गुरुओं ने भी श्रद्धालुओं से अपील की है। स्वामी रामभद्राचार्य ने महाकुम्भ में आने वाले श्रद्धालुओं से अपील की कि वे सभी संगम में स्नान का आग्रह छोड़ दें और निकटतम घाट पर स्नान करें। लोग अपने शिविर से बाहर न निकलें। अपनी और एक दूसरे की सुरक्षा करें। उन्होंने वैष्णव सम्प्रदाय के प्रमुख संत की हैसियत से सभी अखाड़ों और श्रद्धालुओं से अफवाहों से बचने का आह्वान किया।

आत्म अनुशासन का पालन करते हुए सावधानी पूर्वक स्नान करें

बाबा रामदेव ने कहा है कि करोड़ों श्रद्धालुओं के इस हुजूम को देखते हुए हमने फिलहाल केवल सांकेतिक स्नान किया है। इसके साथ ही समूचे राष्ट्र और विश्व के कल्याण की कामनाा की गई है। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि हम भक्ति के अतिरेक में न बहें और आत्म अनुशासन का पालन करते हुए सावधानी पूर्वक स्नान करें। वहीं जूना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी ने भी कहा कि हमने फिलहाल सांकेतिक स्नान किया है।

श्रद्धालुओं की सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी

अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविन्द्र पुरी ने बताया कि इस वक्त 12 करोड़ से अधिक श्रद्धालु प्रयागराज में हैं। इतनी बड़ी तादाद में भीड़ को कंट्रोल करना मुश्किल होता है। हमारे साथ लाखों की संख्या में संतों का हुजूम है। हमारे लिए श्रद्धालुओं की सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है।

सरकार से की अपील, मायावती सहित अन्य नेताओं ने कही ये बातें : अखिलेश यादव

लखनऊ, (संवाददाता)। महाकुंभ में स्नान के लिए मौनी अमावस्या पर प्रयागराज में उमड़ी भारी भीड़ और मची भगदड़ को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से संयम बरतने और मेला प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। वहीं, राजनीतिक दलों के नेताओं ने भगदड़ में मृतकों को श्रद्घांजलि दी और घायलों के इलाज के लिए सरकार से मदद करने की अपील की है। हमारी सरकार से अपील है किरू – गंभीर रूप से घायलों को एअर एंबुलेंस की मदद से निकटतम सर्वश्रेष्ठ हॉस्पिटलों तक पहुंचाकर तुरंत चिकित्सा व्यवस्था की जाए। – मृतकों के शवों को चिन्हित करके उनके परिजनों को सौंपने और उन्हें उनके निवास स्थान तक भेजने का प्रबंध किया जाए। – घ्जो लोग बिछड़ गये हैं, उन्हें मिलाने के लिए त्वरित प्रयास किये जाएं। – हैलीकाप्टर का सदुपयोग करते हुए निगरानी बढ़ाई जाए। – सतयुग से चली आ रही 'शाही स्नान' की अखण्ड–अमृत परंपरा को निरंतर रखते हुए, राहत कार्यों के समानांतर सुरक्षित प्रबंधन के बीच 'मौनी अमावस्या के शाही स्नान' को

संपन्न कराने की व्यवस्था की जाए। श्रद्धालुओं से भी हमारी अपील है कि वो इस कठिन समय में संयम और धैर्य से काम लें और शांतिपूर्वक अपनी तीर्थयात्रा संपन्न करें। सरकार आज की घटना से सबक लेते हुए श्रद्धालुओं के रुकने, ठहरने, भोजन–पानी व अन्य सुविधाओं के लिए अतिरिक्त प्रबंध करे। हादसे में आहत हुए सभी लोगों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना। बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर कहा कि प्रयागराज की संगम स्थली पर, महाकुंभ में हुई भगदड़ में, जिन भी श्रद्धालुओं ने अपनी जान गवाई है व घायल हुए हैं। यह घटना अति–दुःखद व चिन्तनीय है। ऐसे समय में कुदरत पीडिघ्तों को इस दुःख को सहन करने की शक्ति दे, पार्टी की यही कामना। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि महाकुंभ में मौनी अमावस्या के नहान के दिन भगदड़ होने से कई लोगों के मृत और घायल होने का समाचार पीड़ादायक है। यह दुखद घटना इस मेले की अव्यवस्था और उत्तरप्रदेश सरकार की नाकामियों को उजागर कर रही है। योगी सरकार ने सारा पैसा सिर्फ अपनी ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर खर्च किया ना की महाकुंभ में आए श्रद्धालुओं की व्यवस्था पर, ये इस सरकार की संवेदनहीनता को प्रदर्शित करता है। हम लगातार ऐसी ही घटना के प्रति सचेत करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन शासन –प्रशासन के कान पर जूं तक नहीं रेंगा। दुर्घटना के पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। हम मृतकों के आत्मा की शांति व घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं। इसके साथ ही सरकार से यह आग्रह करते हैं कि मृतकों के लिए उचित मुआवजा व घायलों को मुआवजे के साथ मुफ्त इलाज का प्रबंध करे। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि अत्यंत पीड़ादायक घटना प्रभु से प्रार्थना है आज का दिन सकुशल बीत जाय। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को अपने पवित्र चरणों में स्थान दें, उनके परिजनों को ये अपार कष्ट सहन करने की शक्ति दे।

केजरीवाल की अपील, धैर्य और सावधानी बनाए रखें

आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि महाकुंभ में हुई भगदड़ की घटना बेहद दुखद है। इस हादसे में जान गंवाने वाले श्रद्धालुओं की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। ईश्वर उनके परिवारों को यह अपार दुःख सहने की शक्ति दें। सभी श्रद्धालुओं से विनम्र अपील है।

महाकुंभ जा रही श्रद्धालुओं से भरी बोलेरो बस से टकराई, दो महिलाओं की मौके पर मौत

लखनऊ, (संवाददाता)। अमेठी जिले में भीषण सड़क हादसा सामने आया जहां श्रद्धालुओं से भरी तेज रफ्तार बोलेरो कार सामने आ रही रोडवेज बस से टकरा गई। हादसा इतना भीषण था कि बोलेरो सवार तीन महिलाओं समेत सात लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया जहां दो महिलाओं को डॉक्टरो ने मृत घोषित कर दिया जबकि पांच घायलों का अलग–अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है।बोलेरो सवार सभी लोग सिद्धार्थनगर से प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने के लिए जा रहे थे। फिलहाल पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। रामगंज थाना क्षेत्र के अयोध्या प्रयागराज हाईवे स्थित त्रिशुंडी सीआरपीएफ गेट के सामने का है। जहां देर रात करीब 11रू30 बजे श्रद्धालुओं से भरी बोलेरो संख्या यूपी 58 एफ 2770 कि सामने से आ रही रोडवेज बस से भीषण टक्कर हो गई।हादसे में बोलेरो सवार माला पत्नी सूर्यनाथ, सुशील गुप्ता पत्नी हजारीलाल गुप्ता,सूर्यनाथ वर्मा पुत्र कन्हैयालाल वर्मा,गुड़िया पत्नी हरिओम, हजारी प्रसाद पुत्र राम उजागिर,मैना वर्मा पत्नी फूलचंद वर्मा और नरसिंह मिश्रा पुत्र अर्जुन मिश्रा गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही रामगंज पुलिस मौके पर पहुंची।

कतकी मेले में दो दोस्तों पर हमला, तीन गिरफ्तार

लखनऊ, (संवाददाता)। हसनगंज में सोमवार रात मेला देखने पहुंचे बाजारखाला के ठठेरे वाली गली निवासी अयान व उनके दोस्त बिल्लौचपुरा निवासी फाजिल पर शराब के नशे में दबंगों ने चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। अयान के बायें हाथ में चाकू लगा है। उन्हें ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया। पुलिस ने नौ आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर अलीगंज निवासी मोंटू सोनकर, मौलवीगंज के अनूप व हर्ष को गिरफ्तार कर लिया है। अयान के भाई अमान अलीम के मुताबिक दोनों का आरोपियों से किसी बात पर विवाद हो गया था। गाली–गलौज के विरोध पर आरोपियों व उनके छह अज्ञात साथियों ने चाकू से हमला कर दिया।

प्रॉपर्टी डीलिंग के विवाद में पूर्व सैन्यकर्मी पर कातिलाना हमला

लखनऊ, (संवाददाता)। गोमतीनगर विस्तार स्थित गहमर इन होटल में दावत के लिए बुलाकर 25 जनवरी की रात पूर्व सैन्यकर्मी विनय सिंह पर होटल मालिक जगजीत सिंह व उसके दो साथियों सोहन सिंह व जैनुल खान ने जानलेवा हमला किया। आरोपियों ने उनको पिस्टल की बट, बेल्ट व डंडे से पीट दिया। फिर अधमरी हालत में होटल के बाहर फेंक दिया। गंभीर हालत में विनय को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के पीछे प्रॉपर्टी डीलिंग के कारोबार के वर्चस्व का विवाद बताया गया है। गाजीपुर जनपद के करहिया गांव निवासी अन्नु प्रताप सिंह होटल कारोबारी हैं। उन्होंने बताया कि उनके पिता विनय सिंह प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं और पीजीआई इलाके के वृंदावन सेक्टर 10 सी में रहते हैं। पिता के परिचित करहिया गांव निवासी जगजीत सिंह उर्फ नचक भी अपने साथियों गाजीपुर जनपद के गहमर निवासी सोहन व जैनुल के साथ प्रॉपर्टी का काम करते हैं। अन्नु प्रताप के अनुसार, 25 जनवरी की रात तीनों ने उनके पिता को मिलने के लिए होटल बुलाया। वहां सभी ने शराब पी। इसके बाद किसी बात पर विवाद हो गया। एक परिचित ने फोन कर उन्हें बताया था कि उनके पिता घायल अवस्था में होटल के बाहर पड़े हैं और वह उनको कमांड अस्पताल लेकर जा रहे हैं। खबर पाकर अन्नु प्रताप वाराणसी से लखनऊ पहुंचे। इस बीच विनय सिंह को कमांड अस्पताल से दूसरे अस्पताल रेफर कर दिया गया। अन्नु प्रताप ने बताया कि पिता की हालत गंभीर है और वह आईसीयू में भर्ती हैं। 26 जनवरी को उन्होंने तीनों आरोपियों के खिलाफ गोमतीनगर विस्तार थाने में केस दर्ज कराया है।

ड्रेस मेकिंग और सिलाई में रोजगार का अभाव, प्रवेश लेने में इच्छुक नहीं है छात्राएं

लखनऊ, (संवाददाता)। इलेक्ट्रीशियन और मैकेनिकल से आईटीआई करने वाले विद्यार्थियों के लिए तो निजी संस्थानों में रोजगार के अवसर हैं, लेकिन ड्रेस मेकिंग, स्वीइंग टेक्नोलॉजी (सिलाई तकनीक), सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस कोर्स में रोजगार के अवसर न होने से इन कोर्सों में छात्राएं प्रवेश लेने की इच्छुक नहीं हैं। राजकीय आईटीआई में चल रहे इन पाठ्यक्रमों में इस बार भी 50 फीसदी सीटें खाली रह गई हैं। राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद परिषद ने अपनी वेबसाइट पर अलग–अलग आईटीआई पाठ्यक्रमों में प्रवेश की सूची जारी की है। इसमें अलीगंज राजकीय आईटीआई में 25–25 सीटों पर स्टेनोग्राफर, सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस कोर्स में प्रवेश होते हैं। सत्र 2024–25 में केवल 15 सीटों पर ही प्रवेश हो सके। चारबाग आईटीआई में स्वीइंग टेक्नोलॉजी कोर्स में 40 में से 20 सीटें खाली हैं। इसी तरह मलिहाबाद राजकीय आईटीआई में संचालित ड्रेस मेकिंग में भी 40 सीटों के सापेक्ष 21 सीटें खाली रह गई हैं। इन पाठ्यक्रमों में पढ़ रहीं छात्राओं ने बताया कि आधुनिक मांग के आधार पर टेक्नोलॉजी में बदलाव हो रहे हैं, लेकिन ड्रेस मेकिंग व अन्य पाठ्यक्रमों में बदलाव नहीं हो रहे हैं। यही वजह है कि निजी कंपनी और संस्थानों में रोजगार के अवसर नहीं मिल रहे हैं। इन कोर्सों में बदलाव की जरूरत है। अलीगंज आईटीआई के प्रधानाचार्य राजकुमार यादव ने बताया कि एक वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स हैं। पाठ्यक्रमों के आधार पर कंपनी में नौकरी न होने से विद्यार्थी प्रवेश लेने में इच्छुक नहीं होते हैं। हालांकि, मांग के आधार पर नई तकनीकी के बारे में विद्यार्थियों को जानकारी दी जा रही है।

महंगाई ने थाली कर दी खाली, बेलन लेकर उतरीं महिलाएं

लखनऊ, (संवाददाता)। बढ़ती महंगाई के खिलाफ महिलाओं ने मंगलवार को परिवर्तन चौक से कलेक्ट्रेट तक जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। थाली बेलन बजाकर सरकार को आगाह भी किया। कहा कि महंगाई ने उनकी थाली खाली कर दी है। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति (एडवा) के बैनर तले निकले जुलूस में एडवा की राष्ट्रीय संयुक्त सचिव मधु गर्ग ने बताया कि उनकी समिति ने बीते दिनों लखनऊ की 20 बस्तियों और एक गांव के 1600 परिवारों के बीच थाली, शिक्षा व स्वास्थ्य पर महंगाई के पड़ने वाले प्रभाव पर सर्वेक्षण कराया था। उन्होंने सर्वे में पाया कि गरीब परिवारों की स्थिति बहुत दयनीय है। सर्वे में शामिल सभी परिवारों की थाली से दालें लगभग गायब होती जा रही हैं। जिन परिवारों में दाल बनती थी, वहां मटर की दाल कभी–कभी बनती है। ये परिवार हरी सब्जियां भी बहुत कम खरीद पाते हैं। महंगाई का बच्चों की शिक्षा पर भी बहुत असर पड़ा है। एक परिवार के सभी बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। उन्होंने बताया कि आठवीं कक्षा के बाद पढ़ाई बेहद मुश्किल हो रही है। उन्होंने जनता की बुनियादी मांगों से संबंधित मांगपत्र जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को प्रेषित किया। इसमें खाद्य सुरक्षा के तहत आवंटन बढ़ाने, राशन में दालों, चीनी, सरसों के तेल, केरोसिन तेल व अन्य आवश्यक 14 वस्तुओं को शामिल करने, राशन वितरण में बायोमैट्रिक मशीन व आधार लिंक बंद करने, दवाइयों व जनता की बुनियादी जरूरतों की चीजों से जीएसटी हटाने और एक वर्ष में 12 रसोई गैस सिलिंडरों की आपूर्ति सब्सिडाइज्ड रेट पर उपलब्ध करवाने की मांग की। जुलूस में मुख्य रूप से वंदना राय, सुमन सिंह, चंद्रा वर्मा, सुशीला, माया, कैमुन्निसा, शहजहां आदि शामिल रहीं।

संक्षिप्त समाचार

आज से दो जोन में झाड़ू लगाएगी कंपनी

लखनऊ, (संवाददाता)। नगर निगम के जोन 1,3, 4, 6, 7 में सफाई और डोर–टू–डोर कूड़ा कलेक्शन का काम निजी कंपनी लखनऊ स्वच्छता अभियान को नगर निगम ने बीते साल मार्च में दिया था। बुधवार से कंपनी जोन एक व सात में सड़कों की सफाई का काम भी करेगी। अपर नगर आयुक्त पंकज श्रीवास्तव ने बताया कि कंपनी रोड स्वीपिंग की 150 मशीनें लगाएगी। इनमें से 72 आ गई हैं और 12 को ट्रायल के तौर पर चलाया जा रहा है। किसी को सफाई से जुड़ी शिकायत हो तो वह टोल फ्री नंबर 18001234999 पर शिकायत दर्ज कर सकता है।

शिक्षामित्रों के अवकाश मामले में अपर राज्य परियोजना निदेशक ने मांगा जवाब

लखनऊ, (संवाददाता)। लंबे समय से अवैतनिक अवकाश लेकर बच्चों की पढ़ाई प्रभावित कर रहे शिक्षामित्रों के मामले में समग्र शिक्षा अपर राज्य परियोजना निदेशक ने मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक से रिपोर्ट मांगी है। राजधानी सहित मंडल के सीतापुर, लखीमपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली के 270 शिक्षामित्र अवकाश पर हैं। इस मुद्दे को अमर उजाला ने 15 जनवरी के अंक में उठाया था। अब अपर राज्य परियोजना निदेशक एकता सिंह ने मंडल के एडी बेसिक श्याम किशोर तिवारी से रिपोर्ट मांगी है। एडी बेसिक श्याम किशोर तिवारी ने भी सभी बीएसए से शिक्षामित्रों का अवकाश के रिकार्ड सहित पूरा ब्योरा मांगा है। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक शिक्षामित्रों के अवैतनिक अवकाश का विकल्प नहीं है। ऐसे में शिक्षामित्र बिना किसी ठोस कारण के अवकाश लेते हैं तो इससे स्कूल की व्यवस्था पर असर पड़ता है। बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित होती है। बता दें कि कई शिक्षामित्रों को लेकर प्रधानाध्यापकों कहना था कि वह कम मानदेय के चलते अवकाश लेकर दूसरे कार्यों में लगे रहते हैं।

युवक और विवाहिता ने की खुदकुशी

लखनऊ, (संवाददाता)। ठाकुरगंज के अहमदगंज निवासी शादमान (25) ने सोमवार को दोपहर घर में दुपट्टे के सहारे फंदा लगा लिया। मौके से सुसाइड नोट मिला है। इसमें प्रेम–प्रसंग के चलते आत्महत्या करने की बात लिखी थी। घरवालों का कहना है कि शादमान मानसिक रूप से परेशान था और नींद की गोलियों का सेवन करता था। परिवार में पिता कय्यूम, दो भाई और मां हैं। इसके अलावा मड़ियांव के फैजुल्लागंज में यशनगर निवासी आढ़ती इस्माइल की पत्नी सबा खान कुछ समय से हृदय रोग से पीड़ित थीं। उनका इलाज चल रहा था। मंगलवार दोपहर सबा ने कमरे में दुपट्टे के सहारे पंखे से लटककर जान दे दी। परिवार में पति के अलावा दो बच्चे हैं।

500 सीसीटीवी कैमरे खंगाले, लगा डॉग स्क्वॉड, पर बालिका का सुराग नहीं

लखनऊ, (संवाददाता)। दुबग्गा के बरावन खुर्द में बृहस्पतिवार को लापता हुई सब्जी विक्रेता की आठ वर्षीय बेटी का छठे दिन भी सुराग नहीं लगा सका है। पुलिस बालिका के घर से एक किलोमीटर के दायरे में आने वाले मकानों और प्रतिष्ठानों में लगे 500 सीसीटीवी कैमरे खंगाल चुकी है। डाग स्क्वॉड टीम का खोजी कुत्ता कॉलोनी में बने बारात घर तक जाकर लौट रहा है। उधर, बालिका को तलाशने का बीड़ा मोहल्ले की महिलाओं ने उठाया है। महिलाएं अलग–अलग टोलियों बनाकर बालिका की तलाश में लगी हैं। एसीपी शकील अहमद के मुताबिक सर्विलांस समेत तीन टीमें बालिका की तलाश में लगी हैं। पर अभी खाली हाथ हैं। इंस्पेक्टर अभिनव वर्मा ने बताया कि एक फुटेज में तीन संदिग्ध चार पहिया वाहन दिखे हैं। संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। जल्द ही बालिका को सकुशल खोज लिया जाएगा।

संक्षिप्त समाचार

दूसरे चरण की परीक्षाएं 18 से, पांच फरवरी तक भरे जाएंगे परीक्षा फार्म

लखनऊ, (संवाददाता)। डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय (एकेटीयू) की एक तरफ जहां पहले चरण की परीक्षाएं आखिरी चरण में हैं। वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से विषम सेमेस्टर की दूसरे चरण की परीक्षाएं 18 फरवरी से 12 मार्च के बीच प्रस्तावित की गई हैं। मंगलवार को इन परीक्षाओं का प्रस्तावित कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया है। परीक्षा नियंत्रक प्रो. राजीव कुमार ने सभी संबद्ध संस्थानों को इससे छात्रों को अवगत कराते हुए पांच फरवरी तक आपत्ति दर्ज कराने को कहा है। उन्होंने बताया कि दूसरे चरण की परीक्षा में शामिल होने के लिए विद्यार्थी पांच फरवरी तक परीक्षा फार्म भर सकते हैं। उन्होंने बताया कि विद्यार्थी ईआरपी पोर्टल के माध्यम से अपना परीक्षा फार्म भरेंगे। इसके लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क ऑनलाइन जमा करना होगा।

बाइक से टकराई एसयूवी, युवक की मौत

लखनऊ, (संवाददाता)। सर्वोदय नगर बंधे के पास सोमवार रात 11 बजे भाजपा झंडा लगी तेज रफ्तार एसयूवी बाइक से टकरा गई। बाइक सवार सर्वोदय नगर निवासी अकरम (24) और उनके साथी शानू 20 फीट उछलकर सड़क पर जा गिरे। अकरम की मौत हो गई। शानू की हालत गंभीर बनी हुई है। मूलरूप से बिहार के सारन में रहने वाले अकरम अली (24) शानू के साथ किराये के मकान में रहते थे। हादसे के दौरान अकरम हेलमेट पहनकर बाइक चला रहे थे। मौके पर मौजूद लोगों ने कार सवार लोगों को पकड़ने की कोशिश की, पर सभी भाग निकले। हालांकि, एसयूवी चालक हरदोई का शुभम श्रीवास्तव पकड़ में आ गया। पुलिस ने गाड़ी कब्जे में लेकर चालक को गिरफ्तार कर लिया। घरवाले अकरम को लेकर लोहिया अस्पताल ले गए। पांच घंटे तक इलाज में देरी होने पर घरवाले उन्हें निजी अस्पताल ले गए, वहां उनकी मौत हो गई। घरवालों का आरोप है कि लोहिया अस्पताल की लापरवाही के कारण अकरम की मौत हो गई। लोहिया अस्पताल के प्रवक्ता भुवन तिवारी के मुताबिक शिकायत मिलने पर जांच की जाएगी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि एसयूवी सवार लोगों ने हादसे के बाद गाड़ी में लगे भाजपा के कुछ झंडे तोड़ दिए। पर लोगों के दौड़ाने पर आरोपी एक झंडा तोड़ नहीं सके। इंस्पेक्टर गाजीपुर विकास राय के मुताबिक एसयूवी नंबर (यूपी 30 बीएल 1111) अजय कुमार के नाम पर है। अकरम के भाई की तहरीर पर केस दर्ज किया गया है।

बलरामपुर अस्पताल में तीमारदार ने दो गार्डों को पीटा

लखनऊ, (संवाददाता)। बलरामपुर अस्पताल के एसएसबी ब्लॉक में प्रवेश के लिए टोकने पर तीमारदार गार्ड देवेंद्र सिंह से भिड़ गया। तीमारदार ने गार्ड को पटक दिया। इससे उसकी टांग टूट गई। बीच बचाव करने पहुंचे दूसरे गार्ड के सिर में तीमारदार ने डंडा मार दिया। इससे उसका सिर फट गया। स्टाफ घायल दोनों गार्डों को इमरजेंसी ले गया, वहां इलाज के बाद दोनों को भर्ती किया गया। एक गार्ड को परिजन कमांड अस्पताल ले गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी तीमारदार को हिरासत में ले लिया।अस्पताल निदेशक डॉ. सुशील के मुताबिक, घटना 26 जनवरी की शाम की है। ब्लॉक में तीमारदार के पिता भर्ती हैं। पुलिस को पत्र भेजा गया है।

पीएचडी के नौ विषयों का परिणाम जारी

लखनऊ, (संवाददाता)। लखनऊ विश्वविद्यालय ने पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया के क्रम में मंगलवार को नौ और विषयों का परिणाम जारी कर दिया। अभ्यर्थी लविवि की वेबसाइट पर विस्तृत कटऑफ सूची देख सकते हैं। प्रवेश समन्वयक कार्यालय ने पत्र जारी कर परिणाम घोषित किए जाने की जानकारी दी। प्रवक्ता प्रो. दुर्गेश श्रीवास्तव ने बताया कि जिन विषयों के परिणाम जारी हुए हैं, उनमें एनवायरनमेंट साइंस, पब्लिक हेल्थ, बॉटनी, मेडुअल एंड मॉडर्न हिस्ट्री, एशियन इंडियन हिस्ट्री एंड ऑर्कियोलॉजी, अरब कल्चर, केमेस्ट्री, अप्लाइड इकनॉमिक्स व अरबी शामिल हैं। इसमें सीटों के सापेक्ष चयनित अभ्यर्थी पूर्व में दी गई।

लखनऊ में बड़ा हादसा, दुकानों में घुसा अनियंत्रित ट्रक, तीन लोगों की मौत और कई घायल

लखनऊ, (संवाददाता)। इटौंजा से कुर्सी रोड की ओर जा रहा तेज रफ्तार कंटेनर मंगलवार रात अनियंत्रित होकर सड़क किनारे मौजूद दुकानों पर पलट गया। कंटेनर के नीचे दुकानदार और ग्राहक दब गए। हादसे में महोना नगर पंचायत के तीन युवकों की मौत हो गई, जबकि पांच अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। कंटेनर पर फ्रूटी लदी हुई थी। इसकी वजह से राहत एवं बचाव अभियान में पुलिस और स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इंस्पेक्टर इटौंजा के मुताबिक हादसे में महोना के शिवा (18), संजीव (18) और धनेश (22) की मौत हुई है। वहीं, महोना के ही मुन्ना, नीरज और मनीष रावत गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें सीएचसी में भर्ती कराया गया है। इनके अलावा दो अन्य लोगों को ट्रामा सेंटर रेफर किया गया है, जिनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। कंटेनर की रफ्तार इतनी तेज थी कि उसके पलटते ही दुकानें जंमीदोज हो गईं। मलबे में और लोगों के दबे होने की आशंका को देखते हुए एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया। देर रात में कंटेनर को किनारे कर मलबे को जेसीबी से हटाने का काम शुरू हुआ। हादसा मंगलवार रात करीब 10 बजे का बताया जा रहा है।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक
श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव
मो0 - 7007415808, 9628325542, 9415034002
RNI NO - UPHIN/2022/86937
Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से संबधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।